साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

पंजीयन क्रमांक RNINDPM\HIN\16730/12/1/97/TC

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Tel : 91-731-2102725
Cell : 91-9827330697
Fax : 91-731-2531630
Websites : www.corruption2india.com
www.geocities.com/ corruption2india/ eduIndore.html
www.geocities.com/corruption2india/ corruptindia.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com

वर्ष 6 अंक 42 | इन्दौर, जबलपुर सोमवार, 20 से 26 दिसंबर 2004 | पृष्ठ 8 मूल्य रु.2/-

2 संपादकीय ✦मानवाधिकार आयोग को इन पर ध्यान देना होगा

3 ✦नर्मदा पाइप लाइन फूटी या फोड़ी गई ✦सेना घटाकर सुरक्षा एजंसियों की मौत को दावत

4 ✦भ्रष्ट वा. कर में भ्रष्टोन्नति के कारनामे ✦मत्स्य विबाग में रायल्टी में घोटाला

5 ✦वि.वि. बन चुके हैं अय्याशी के अड्डे ✦चौपाल से खरीदी का अधिकार क्यों?

7 ✦सर्व शिक्षा लूटो अभियान

8 ✦प्रौढ़ महिलाओं में बढ़ रही अय्याशी ✦ मंत्रियों का इंदौरी प्रेम

ईराक में अमेरिकी आतंक (भाग-2)

ईराक में अमेरिकी तांडव कब बंद होगा?

विश्व के सभी बड़े और मुस्लिम देश चुप क्यों हैं?

अमेरिका में बुश की जीत क्या हुई उसने ईराकी शहर फल्लुजा पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। भीषण नरसंहार में और तो और दुधमुंहों को भी नहीं बख्शा जा रहा। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि विश्व की विश्व व्यापी संस्था संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान भी चुप्पी साध रखी है दूसरी ओर विश्व का मुस्लिम लड़ाकू समुदाय होने के बाद भी उसका खून भी जम गया है। भारत की कांग्रेसी संयुक्त दलों की सरकार तो वैसे भी अमेरिकी कठपुतली रही है। इन भिखारियों को तो हड्डी डाल दो चुपचाप देश की जनता नोचकर हड्डियां बोटियां चूसते बैठेंगे। रुस, चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी शांत बैठे हैं। आश्चर्य है पूरा विश्व अमेरिकी गुंडों के सामने झुका हुआ है।

संकर प्रजाति अमेरिकियों ने ओसामा के जाली टेप के सामने घुटने क्या टिकाए, बुश छुट्टे सांड की तरह आतंक बरपा कर उसने ईराक फल्लुजा शहर में भीषण तबाही मचाना शुरू कर दी। ईराकियों के ठोस और गुरिल्ला प्रतिरोध के अभाव में सैंकड़ों बेगुनाह ईराकियों जिसमें हजारों महिलाएं और बच्चों को भी सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है, पर चारों तरफ चुप्पी है। कोई भी उक्त गुंडे के विरुद्ध मुंह नहीं खोलना चाहता। आश्चर्य तो इस बात का है कि इतने भीषण नरसंहार के सामने विश्व की लड़ाकू समझे जाने वाली विश्व की सैंकडों मुस्लिम देशों और जनता ने भी उसका न तो विरोध किया और न ही वहां की आक्रांत जनता के और मरने वालों के प्रति विरोध प्रदर्शित किया न ही सहानुभूति दिखाई। क्या हो गया, कहां गए जेहादी केवल कश्मीर को ही नोंचने-खसोटने के लिए पैदा हुए हणैं क्या? इराक में जाकर अमेरिकी गुंडागर्दी, आतंकवाद और भीषण नरसंहार के प्रति भी जहां सचमुच इस्लाम खतरे में है कुछ जेहादी शक्ति प्रदर्शन करो। अमेरिकी गुंडे बुश का नाकों चने चबबा दो। परन्तु वहां की जनता कुछ मुट्ठी भर जाबांजों के दम पर दिन-रात भीषण, नरसंहार, हेलिकाफ्टरों, लड़ाकू विमानो तोपों और फौज की चारों तरफ से बरसती गोलियो में पल-पल बरसती मौत में दिन में गुजार रही है।

ईराकियों के कमजोर पड़ते प्रति आक्रमण और घटती प्रतिरोधक क्षमता भविष्य में इराक को वियतनाम से कमजोर सिद्ध कर देगी। वियतनाम के मुट्ठी

(शेष पेज 6 पर)

एड्स-भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की साजिश

10 पै. के फुग्गे को 10 रु. में बेचने की और देश की नपुसंक बनाने की साजिश

शंकर प्रजाति के मानवों के देश अमेरिका ने जो पूरी दुनिया में एड्स को शगूफा छोड़ पूरी दुनिया को जो टोपी पहनाने की साजिश रची है उसका मूल उद्देश्य कोई बीमारी, एच.आई.वी. जैसी बात तो नहीं वरन इसके विपरीत पूरी दुनिया के विशेष रूप से पूरे भारत को नपुसंक बनाने की साजिश ही प्रतीत होती है।

भारत के और हमारे आयुर्वेद भगवान विष्णु के साक्षात अवतार समझे जाने वाले धनवंतरि ने भी अपने प्राचीन ग्रंथों में ऐसी किसी बीमारी के बारे में नहीं लिखा जबकि डी.एन. ए. जैसी कोशिकाओं और एक ही कोख से जन्मे भाई-बहन के आपसी संभोग से उत्पन्न होने वाली पीढ़ियों में विकृति को रोकने के लिए उसे पाप बनाकर हर चार माह के बाद पड़ने वाली दूज को भाई दूज बनाकर भाई-बहन के बीच शारीरिक दूरी को बनाए रखा। इसकी सूक्ष्म मीमांसा में यौन संबंधो से विकसित होने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हो जाने वाली विकृतियों को प्रतिबंधित करना ही था पूरे यूरोप को भारत के बढ़ते प्रभाव और काश्मीर को भारतीय सेनाओं द्वारा 50 वर्ष बाद भी बचा कर रखने के विरुद्ध सेना का मनोबल तोड़ने के लिए इन विदेशियों के साथ भारत शासन में बैठे उस सोनिया के इशारे पर सेना का मनोबल तोड़ने के लिए भारतीय सेना में ही एड्स का शिगूफा फैलाकर सेना को और उसकी आड़ में पूरे देश को ही कमजोर बनाने की साजिश है।

एड्स दिवस 1 दिसंबर के रूप में मनाए जाने की ही तो विदेशी षड्यंत्र के सौगात थी पूरे देश को कि इन शूकरों की फौज के साथ भारत शासन और पूरे देश का मीडिया भारतीय सेना और उसके पीछे पूरे देश का मनोबल तोड़कर देश की रक्षा पंक्ति के साथ पूरे देश को ही सामारिक रूप से कमजोर सिद्ध कर दे।

अब जबकि देश पर षड्यंत्रकारी युरोपियन समुदाय की एजेंट सोनिया का शासन है तो स्वाभाविक है देश को हर प्रकार से कमजोर असहाय और नपुसंक बना दिया जाए। एड्स की आड़ में एड्स का कंडोम पहनाकर देश के पुरुष वर्ग को जो पृथ्वी के हर कोने में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। पूर्णत: नपुसंक बनाकर पुन: गुलाम बना लिया जाए।

एड्स कौन सी बीमारी है एच.आई.वी. के कौन से जीवाणु हैं अभी तक कोई सही व्याख्या इसलिए नहीं कर पाया कि सचमुच वह बीमारी नहीं वरन 10 पैसे के कंडोम को रु. 10 में बेचने के षड्यंत्र के साथ देश के पुरुषो

(शेष पेज 6 पर)

भाजपा शासन की 1 वर्ष की उपलब्धियां

भ्रष्टाचार बढ़ा, बिजली की कीमतों में वृद्धि की, पूंजी पतियों की रखैल

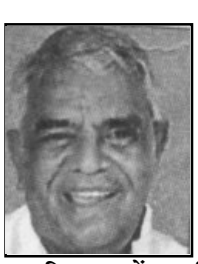

भाजपा शासन काल में प्रदेश में जिस दम पर भाजपा जीत कर आई थी भ्रष्टाचार और बिजली कटौती दोनों ही बढ़ीं। भाजपा शासन से अपेक्षा थी कि वो नए जल विद्युत, ताप विद्यत गृहों का निर्माण कर बिजली की कमी का स्थाई हल निकालेगी उल्टा गौर रिलायंस के टूटते उजड़ते आशियाने में बार-बार दस्तक देकर दिग्गी दानव की तरह अपना कमीशन सेट करने में लगा है। भ्रष्ट अधिकारियों की पौ-बारह हो रही है। भ्रष्ट मंत्री मूछों पर ताव दे रहे हैं। डंके की चोट पर लूट-खसोट में लगे हैं। ये है एक वर्ष की उपलब्धियां

भोपाल। भाजपा ने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा अवश्य कर लिया। उपलब्धियां उसके खाते में आईं उसने एक मात्र काम जो अच्छा किया दिग्गी दानव की गड्ढेदार सड़कों पर थिगड़े लगा कर भराई करवा दी और उस पर लीपा-पोती कर डामर का लेप चढ़ा दिया, जो बरसात आते ही अपनी सच्चाई बयान करने लगी कि उसमें किस स्तर का कैलाश विजयवर्गीय से लेकर पूरे म.प्र. के इंजीनियर इन चीफ, मुख्य अभियंताओं से लेकर सुपर वाइजरों तक ने वर्षों बाद आए पैसे को दोनों हाथों से लूटा। नि:संदेह यदि 50 प्रतिशत पैसा लूट में गया तो 50 प्रतिशत का काम पूरे प्रदेश की सड़कों पर देखा जा सकता है।

कानून शिक्षित बाबू गौर ने सत्ता संभालते ही साथ भ्रष्टाचारियों को खुल कर संरक्षण दिया। सचिवालय से लेकर नीचे बाबू और चपरासियों तक जितने भ्रष्ट जहां थे वहीं जमे रहकर नई सरकार को भी जी भर उसके संरक्षण से जनता से, जनता के शासन का धन का दोहन करने में लगे रहे। फिर बात चाहे बिजली की हो, पानी की, सड़कों, आबकरी, परिवहन, खाद्य, नाप-तौल, महिला एवं बाल विकास, भू-अभिलेख, मुद्रांक पंजीयन, कृषि, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, नर्मदा विकास प्राधिकरण, 48 नगरों के विकास प्राधिकरणों, उद्योग विभाग, वाणिज्य कर, अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वास्थ्य, जन संसाधन, पंचायत जैसे शासन के सभी विभागों में बैठे लुटेरे गिद्धों की फौज को उमा की नासमझी, उकताहट, पूजा पाठ, दूरदर्शिता की कमी ने बढ़ावा दिया, तो गौर की धूर्तता भ्रष्टाचार और वसूली की नियत ने बढ़ावा दिया।

जबकि भाजपा के केन्द्र के परिणामों से राज्य स्तर पर तो ठोस तरीकों से त्रिआयामी कार्य करना चाहिए था ताकि न केवल भ्रष्टाचार रुक सके, दूसरे पुराने पापियों के भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर सबसे पहले ऐसे हरामखोर, धूर्त, भ्रष्ट, मक्कार सचिवों, आयुक्तों, संचालकों से लेकर जिलाधीश पदों पर बैठे आई.ए.एस. की फाइल खुलवाकर कार्यवाही करना चाहिए थी। पुराने पूर्व सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री आदि के पूरे कांडों का पर्दाफाश कर जनता के सामने जनता के धन का किस तरह दुरुपयोग किया गया, खोल कर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किए जाते तो न केवल भविष्य में ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती थी वरन जनता के धन का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता था।

द्वितीय स्तर पर वर्तमान में जनता

(शेष पेज 6 पर)

सोनिया का षड्यंत्र-देश की चहुंमुखी बर्बादी करेगा

सास स्व. इंदिरा और पति स्व. राजीव गांधी की हत्या में सोनिया के षड्यंत्रों की गहराई तक पहुंचते ही भारतीय अनुसंधान एजेंसियो के हाथ पैर फूलने लगते हैं। विदेशी धमकियां और धन का आक्रमण के सामने सब असहाय हो जाते हैं क्या न्यायालय और क्या पुलिस, सीबीआई, रॉ.

सास स्व. इंदिरा और पति स्व. की राजीव की हत्या के बाद अंत्येष्टि संस्कारों तक में सोनिया के चेहरे पर कहीं कोई शिक़न परेशानी या दुख नजर नहीं आया जो पूरे देश के लोगों ने वीडियो कैमरे के माध्यमों से देखा। वहीं दूसरी तरफ प्रेमी स्व. माधवराव की मौत पर सोनिया और बेटी प्रियंका के आंसू भी पूरी दुनिया ने टीवी पर देखे। क्या यही भारतीय बहू की पहचान है।

यूरोपियन मुख्य रूप से अमेरिका, इंग्लैंड और इटली की जासूसी संस्थाओं की ये एजेंट उन्हीं के इशारों पर देश और हिन्दुत्व की बर्बादी पर तुली है। कश्मीर में सेना घटाना भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी संस्थाओं की भारी

(शेष पेज 3 पर)

साप्ताहिक समय माया

सम्पादकीय

मानवाधिकार आयोग को इन पर ध्यान देना होगा?

डाक्टरों पर-डाक्टर सेवा की शपथ लेकर डाक्टर अवश्य बन जाते हैं, परन्तु डाक्टर बनते ही डाक्टरी की कमत वसूलने के लिए शादी करते समय मोटा दहेज चाहिए होता है। (2) नर्सिंग होम्स में कमीशन खाने की प्रवृत्ति के चलते मरीजों के अनावश्यक परीक्षण करवा कर मरीज को मोटा मरीज बनाकर जिसे बीमारी बढ़ाकर बड़े नर्सिंग होम्स में भेजकर वसूली करते हैं। (3) छोटी सी बीमारी यहां तक कि पेट दर्द के मरीजों का अपेन्डिक्स आपरेशन कर मोटी वसूली करने के बाद भी किडनी चुरा लेने तक की घटनाएं की जाती हैं। जैसे इंदौर का डॉ. विनोद भंडारी, भंडारी नर्सिंग होम, अरबिन्दो मेडिकल कालेज, जबलपुर का डाक्टर धीरावाणी जबलपुर नर्सिंग होम चलाने वाले इन हजारों गिद्धों पर मानव अधिकार आयोग को ऐसे हरामखोरों को न केवल प्रेक्टिस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए वरन सजाएं भी दिलवाई जानी चाहिए। (4) नर्सिंग होम लूट के अड्डे बन चुके हैं। अनावश्यक रूप से आईसीयू में भर्ती करके लूटना, कमरों के किरायों के नाम पर रु. 500 से 5000 तक वसूलने जैसी लूटों पर प्रतिबंध लगाए जाना चाहिए। किराये रु. 100 से 500 तक प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। (5) नर्सिंग होम में नर्सों और महिला मरीजों को यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। (6) शासकीय एवं निजी नर्सिंग होम में साफ-सफाई, वातानुकूलन कमरे होना चाहिए। इसके विपरीत शासकीय अस्पतालों में और निजी नर्सिंग होम्स में गंदगी का वातावरण तो होता ही है। मरीजों को निजी नर्सिंग होम्स में लूटने के लिए तलघरों में बिस्तर लगा कर लेटा दिया जाता है जहां साधारण मरीज की देखभाल करने वाले भी बीमार हो जाते हैं तो बीमारों का क्या हाल होता होगा, कल्पना की जा सकती है। (7) मरीजों को दी जाने वाली औषधियों, जिसमें गोलियां इंजेक्शन, केप्सूल आदि की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाना चाहिए इंदौर में 400 से ज्यादा नकली, स्तरहीन मिलावटी, सामानांतर औषधि निर्माता हैं। तत्काल प्रभाव से इन्हें रोका जावे, क्योंकि अधिकांश ऐसी दवाओं का प्रयोग मरीज को साधारण से गंभीर बीमार बना देता है। (8) जो डाक्टर डाक्टरी पेशे का प्रयोग केवल प्रमाण पत्र बनाने में करते हैं उनकी डिग्रियां तत्काल र- की जानी चाहिए। कुछ डाक्टर तो आरटीओ में एक ब्रीफकेस से ही सारा कारोबार चलाते हैं। (9) जो डाक्टर अपने पेशे के प्रति लापरवाह हैं शासकीय और निजी निर्सिंग होम में जिनकी लापरवाही से मरीजों के मर्ज बढ़ने लगते हैं या मौत हो जाती है उनकी तत्काल गिरप्तारी और कोर्ट में चालान पेशकिए जाने चाहिए ताकि दूसरे हरामखोरों, मक्कारों को सजा का सबक मिल सके। (10) जितने भी लालची गिद्ध डाक्टर डाक्टरी पेशे में हैं उनकी डिग्रियां भी तत्काल र- की जानी चाहिए। जो मर्ज को गंभीर मर्ज में बदलकर लूटने में लगे हैं उनकी डिग्रियां भी र- की जानी चाहिए।

शिक्षा पर- मानव अधिकार आयोग को शिक्षा में बढ़ती व्यावसायिकता, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, यौन शोषण और जालसाजियों को रोकना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन का जन्म और पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है। यदि एक बढ़ते हुए बच्चे से सिक्षा के नाम पर कदम-कदम पर छल, कपट, भ्रष्टाचार, बेईमानी और यौन शोषण का सामना करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है वह उसके मस्तिष्क पर जीवन पर्यन्तसर डालेगा ही उसके दुष्परिणाम न केवल उस बच्चे के जीवन को प्रभावित करेंगे वरन उसके दुष्परिणाम समाज को भ्रष्टाचार, अपराध, लूट, खसोट के रूप में समाज को भी भोगने पड़ेंगे। बच्चों पर लादे जाने वाले बस्तों का बोझ कम करने के साथ ही ावश्यक है बच्चों के साथ उनके पालकों पर स्कूल कालेज संचालकों द्वारा किया जाने वाला व्यवसायीकरण अनाप-शनाप वसूलियां, छल-कपट भी रोका जाए।

पुलिस पर- मानव अधिकार आयोग के पास पुलिस ज्यादतियों की सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, पर पुलिस को इससे कोई खास असर नहीं पड़ता। जबकि पुलिस ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, लूट-खसोट के चलते मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करती, खुद वर्दी पहन लेने के बाद खुले में मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और अपनी पोल खुलते देख निर्दोषों को भी मौत के घाट उतार देती है। शासन भी उसकी हर तरफ से अनदेखी कर खुले में उसके हर अपराध को संरक्षण देती है जबकि आवश्यक यह होता है कि उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच बैठा कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि दूसरे वर्दीधारी सबक सीख सकें और भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। मानवाधिकारों के उल्लंघन हर क्षेत्र में हो रहे हैं। चाहे वह बाजार हो, न्यायालय हो, शैक्षणिक संस्थान, औषधालय, चिकित्सालय, शासकीय कार्यालय, रेल्वे स्टेशन पर खुले में शक्तिशाली अधिकार संपन्न का शोषण करते हैं, जिनके बारे में अगले अंकों में प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

(पेज 5 का शेष) विश्वविद्यालयबन चुके हैं.....

इन बदतमीज हरामखोरों ने प्रयोगशाला की मशीनों के रखरखाव का लाखों रुपया वर्षों से डकारा परिणाम स्वरूप मशीनें, उपकरण आदि मिट्टी का ढेर हो गए। विद्यालय में विद्यार्थी के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं। डॉ. देशराज जैन, डॉ. श्रीवास्तव ने मिलकर छात्रों की एक सेमेस्टर की परीक्षा ही जानबूझकर जालसाजियों और षड्यंत्र के तहत नहीं करवाई, ताकि खाली पड़ी अगली कक्षा की सीटों पर दूसरे निजी कालेज के छात्रों से पैसा लेकर बैठाया जा सके। ये दोनों धूर्त सूकर कितने मक्कार हैं। इनकी इन कारगुजारियों से पता चलता है। विश्वविद्यालय कुलपति, राज्यपाल तक से छात्रों ने शिकायत की परन्तु सारे के सारे हैं तो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे। सबको हर कार्य के लिए पैसा चाहिए।जिस महिला प्राध्यापक, सह प्राध्यापक को जो छात्र पसंद आ गया उसे वो किसी भी तरह से निचोड़ेगी फिर ये कहानी एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीडीएस, है वही हाल पुरुष प्राध्यापकों का है। यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो ये विद्यार्थियों को वर्षों अनुत्तीर्ण करके लटकाया करते हैं। एम फिल और पीएचडी करने वाली लड़कियों का पुरुष प्राध्यापक या जिसके अंतर्गत ये पाठ्यक्रम पूरे किए जा रहे हैं अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो हवस के बूखे दरिंदे किसी भी हद तक उतर कर विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करने से नहीं चूकते। इसीएि पूर्व के कुलपति ने कहा था इंदौर विश्वविद्यालय में पढ़ाने से बेहतर लड़की को जहर देना पसंद करेंगे। सभी महिला छात्रावासों की यौन स्वच्छंदचारिता के किस्से आए दिन समाचार-पत्रों में छपे ही रहते हैं। ऐसे छात्रावासों के वार्डन्स भी इन तरीकों से कमाई करते और सप्लाई का व्यवसाय करने से नहीं चूकते।

क्या विश्वविद्यालय प्रशासन और कांग्रेसी थाकड़ राज्यपाल इस ढर्रे को सुधार देंगे?

पंपों पर मिलावट कम तौल की लूट पर छूट

गैस एजेंसी मालिकों को ब्लेक मार्केटिंग की छूट, गैस वाहनों से हो रही लूट

कासट
कसता वसूली का शिकंजा

शासन के अधिकारी और कर्मचारी अपनी-अपनी कमजोरियों को छुपाने, भ्रष्टाचार और अपने कुकर्मों को तो दबाने के लिए जनता द्वारा निकाले अपनी सुविधा के परिणामों पर आघात करते हैं। ऐसा ही कुछ गैस चलित वाहनों के साथ किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म नहीं किया जाता परिणामों पर अधिकारी और कर्मचारी अपनी वाहवाही व रौब झाड़ते हैं।

सीएल जाटव
पेट्रोल पंप प्रभारी
मिलाओ कितना मिलाओगे

गैस से वाहन अकेले इंदौर में ही चल रहे हों न तो ऐसा हो रहा है पूरे देश में चल रहे हैं। हरामखरों उनको भी देखो दूसरा सर्वोच्च न्यायालय एक तरफ सीएनजी से वाहन चलाने का आदेश देता है ताकि वायु प्रदूषण न फैले दूसरी तरफ इंदौर में गैस से चलने वाले वाहनों की पकड़ा धकड़ी होती है। गैस की ब्लेक मार्केटिंग कांग्रेस व केन्द्रीय शासन की वर्तमान नीतियों की बदतमीजी और लूट के कारण हो रहा है न कि वाहनों में उपयोग के कारण।

दूसरा पूरे शहर के पेट्रोल पंपों में मिट्टी का तेल, नेप्था, हेक्साजीन, फर्नेस ऑइल तो खुद भ्रष्ट खाद्य विभाग वाले मिलवा रहे हैं। नाप तौल वाले अपनी वसूली कर खुले में कम नापने का लायसेंस दे रहे हैं। जनता अगर उनसे बचने के लिए गैस के सस्तेपन और प्रदूषण रहित होने के कारण उपयोग कर क्या गलती कर रही है। गैस रसोई में जले तो या वाहन में चले तो मुफ्त में तो नहीं मिल रही।

गैस पर अनुदान देने की बात भ्रष्ट शासकीय शगूफे बाजी और जनता को भ्रमित कर शोषण का हथियार बन चुका है। अपनी लूट, भ्रष्टाचार को ढांकने का मक्कारों, हरामखोरों अनुदान कांग्रेस या भाजपा अपने जेब से दे रही है क्या?

इंदौर। 3-4 दिस. को खाद्य और भ्रष्ट पुलिस ने मिलकर गैस चलित 160 वाहन लगभग पकड़े मीडिया भी खुश और भ्रष्ट खाद्य व पुलिस विभाग ने जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो वह भी खुश। जबकि ये दोनो हरामखोरों और भ्रष्टों की फौज कितनी ईमानदार है यह दुनिया जानती है।

गैस वालों से वसूली फिर उपयोग करने वालों से भी

खाद्य विभाग और पुलिस ही है जो मिट्टी के तेल की कालाबाजारी पार्षदों के साथ मिलकर करवाती है। थोक में मिट्टी का तेल खरीद कर आटो जीप, ट्रकों और बसों को बेचा जाता है। उस समय भी कमाती है और फिर प्रदूषण के नाम पर ऐसे मिट्टी का तेल चलित वाहनों को पकड़कर उनके चालान बनाकर भी पैसे ऐंठती हैं। अर्थात मौत फिर भी जनता के वाहन चालकों को वो रु. 10 का मिट्टी तेल रु. 20 में खरीदें फिर इनकी बदतमीजियां भी झेले। चाहे वाहन चालकों को दो वक्त की नसीब हो न हो।

पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल में खुले में मिट्टी का तेल, साल्वेंट हेक्जीन, नेफ्था, फर्नेस ऑइल की मिलावट होती है जो स्वयं खाद्य विभाग के जिला खाद्य नियंत्रक कासट और उसके भ्रष्ट चेलों को मासिक वसूली देते हैं। मि. सुलेमान ने पेट्रोल पंपों पर मिलावट रोकने के लिए कंपनी से आए टैंकर को खाली करवाने के बाद सील लगवाने की व्यवस्था की थी ताकि मिलावट न हो, परन्तु भ्रष्ट कासट ने भ्रष्ट पेट्रोल पंप मालिकों को खुले में मिलावट करने की छूट दे दी। अब वाहो ई सहायक खाद्य नियंत्रक पेट्रोल पंपों पर टैंकर खाली करवाने या सील लगाने नहीं जाता। हैं शहर के 80 में से 70 मिलावटिये जिसमें कुछ तो मिलावट के कुख्यात हैं जिसमें पूरे एमजी रोड, आर.एन. टी. मार्ग, ए.बी. रोड, खातीवाला टैंक के जिसमें नरोत्तम दास, अशोक, वी.एम. मोदी, बी.एम. एंड संस, जिनके पास खुद की मिट्टी तेल की डीलर शिप है वो कम मिट्टी का तेल बांटकर बचे हुए को सीधा 40 रु. लीटर के पेट्रोल में मिला देते हैं। फिर रिलायंस पेट्रोलियम के प्रतिदिन 20 से 40 टैंकर जो गुजरात से कम आवंटन का साल्वेंट, फर्नेस ऑइल लेकर पिटोल से घुसकर सब इंदौर में ही खाली होती है।

खाद्य विभाग का कहना पड़ता है कि हम क्या कर लेंगे सेंपल्स भर कर भी मिलावट में मिट्टी का तेल 40 प्रतिशत तक मिलाकर भी भेजा तो क्लीन चिट मिल गई तो फिर उन भ्रष्टों से वसूली ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है।

फिर मिलावट तो ठीक पेट्रोल पंपों के कर्मचारियों को कम नापने से कहां चूकते हैं। उज्जैन में पेट्रोल पंप के मीटर जंप करते हैं। रु. 12 तक दिखा फिर सीधा रु. 32 पर पहुंच गया कहोगे तो हॉकरों से लड़ाई होगी।

इंदौर के नाप-तौल में बैठा अजीत श्री वास्तव हर महीने रु. 5000 प्रति पेट्रोल पंप वसूल करके चुप हो जाता है। वह हाल पाटनकर का भी है। अजीत श्रीवास्तव घर से निकलकर 10.30 बजे तक केवल पंपों से ही वसूली करता है। हर दिन बस दो-तीन पेट्रोल पंपों से नोट गिनते श्रीवास्तव की फोटो हमारे कैमरों में कैद है। पलासिया के पेट्रोल पंप पर 10.05 मिनिट की अक्टूबर माह की दिनांक 5-10-04 की।

अब जब वाहन चालकों के साथ पेट्रोल पंप मालिक कदम-कदम पर लूट करेंगे तो वाहन चालक स्वाभाविक है सस्ते विकल्प के रूप में गैस से वाहन चलाए तो क्या गलती कर रहा है। फिर दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय कहता है वाहन गैस से चलाओ।

इंदौर में पुलिस और खाद्य विभाग उनकी जब्ती बनाता है जो जनता क्या मर जाए। या वाहन न खरीदे। गैस डीलर चाहे मंडल श्री गैस ओ इंडेन, सत्यम व सभी 25-27 गैस की ब्लेक कर रहे हैं तो खाद्य विभाग की महीना भी दे रहे हैं। फिर केन्द्रीय सरकार की नीतियां भ्रष्टाचार और लूट के लिए ही बनाई जा रही हैं तो हरामखोरों उनकी बदतमीजियों को रोको ना।

बीएसएनएल भी निकम्मे, हरामखोरों की फौज

बिल जमा होने के बाद भी सैंकड़ों फोन काटे, सिम के आश्वासनों के पुलिंदे

भारत की 150 वर्ष पुरानी दूरसंचार सेवाएं जो अब भारत संचार निगम के नाम से जानी जाती हैं। अधबूढ़े मक्कारों, कामचोरों और भ्रष्टों की फौज भरी है। नेहरू पार्क में बैठी महिला कर्मचारियों से सारे दिन गप्पे लगवा लो, स्वेटर बुनवा लो और काम के नाम पर 2 दिस. को बिना बताए ही बिल जमा होने के बाद भी सैंकड़ों फोन काट दिए गए और जब कहने गए तो ये निकम्मी फौज जो मुफ्त का वेतन लेकर निगम को डुबोने लगी है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने का नाटक दिखाने लगी।

आवेदन देने के बाद भी निगम के महाप्रबंधक निगम कार्यालय में भी झूठे आश्वासनों के अतिरिक्त कुछ नहीं। घर पर फोन करो और बच्चे उठा ले तो बाप की अफसरी झाड़ने लगते हैं।

इंदौर। पूरे देश के केन्द्रीय और राज्यों के शासन तंत्र में अधबूढ़ी मक्कार, कामचोर और भ्रष्टों का बोलबाला है। इन हरामखोरों का विश्व व्यापार संगटन की छंटनी की लटकती तलवार नहीं दिख रही है। न जनता का बढ़ता आक्रोश और बाजार वाद की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से ये सारे भ्रष्ट शूकरों की फौज बिल्कुल चिंतित नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है केन्द्रीय शासन का डाक तार विभाग, भारत संचार निगम लि. जो पूर्व में पोस्ट एंड टेलीग्राफ का हिस्सा था बाद में भारतीय दूर संचार और अब भारत संचार निगम लि. बन गया है। अपने आप को 150 वर्ष पुरानी सेवा कहते हुए भले ही इन मक्कारों को शर्म आती हो न हो, परन्तु वर्तमान पीढ़ी को ये सुनने और पढ़ने में अवश्य शर्म आने लगी है। कि महीनों बाद भी आवेदनों पर सुनवाई नहीं आवेदन गुम हो जाना, फिर जहां महिलाएं बैठी हों तो फिर मानकर ही चलिए कि ये महाभ्रष्ट, मक्कार, कामचोर फौज नौकरी करने तो नहीं वरन घर में पति, बच्चों, मां-बाप और सास-ससुर के तानों, काम से बचने और समय व्यतीत करने के बहाने हर महीने मिलती मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए आती हैं। आते ही साथ मेरी साड़ी से तेरी ज्यादा सफेद कैसे? तेरे घर में ये है मेरे पास ये नहीं तेरा पति मेरे पति से ज्यादा मूर्ख है। या स्वेटर बुनने और गप्पे ही मारने आती है। ये कामचोर पौज लंच के लिए 1 बजे से काम बंद करती हैं तो तीन बजे लौटती हैं। 5.30 बजे जाने के लिए 4.30 बजे से पेन बंद और जाने की तैयारी शुरू और 5 बजे सारा स्टाफ़ गायब। इन्हीं के बदतमीजियों का परिणाम था सैंकड़ों उपभोक्तों के पैसे जमा होने के बाद भी इन बदतमीजियों और भ्रष्टों ने 2 दिसंबर को बिना बताए हजारों टेलीफोन काट दिए। वो भ्रष्ट शूकर इस निगम का इंदौर का महाप्रबंधक निगम भी कुछ सुनने को तैयार नहीं ये हरामखोर तो बहानेबाजी और मक्कारी में भी अव्वल हैं। फिर ये तो ये इसके पिल्ले-पिल्लियां भी एक तो फोन उठाएंगे बात करो तो सबके सब मक्कार बाप की औलाद अफसरी झाड़ने लगेंगे। बेचारा उपभोक्ता गिड़गिड़ाता रहेगा। पैसे जमा करने के बाद भी फोन काटना। ये सब अधबूढ़ी फौज चाहती है कि टाटा, रिलायंस, एयर टेल के पास सारे कनेक्शन चले जाएं तो भी शासन की

(शेष पेज 3 पर)

नर्मदा पाइप लाइन फूटी या फोड़ी गई

सीमेंट के घटिया स्तर की पाइप लाइन बार फूटेगी नहीं तो कमाई कैसे होगी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में चारों ओर भ्रष्टों का बोलबाला है। जलूद से नर्मदा जल लाने के लिए अंदर बाहर सीमेंट चढ़ी 1200 मिमी की कच्चे ढलवा लोहे की पाइप लाइन डाली जानी टाहिए थी जिसके स्थान पर खाली सीमेंट की घटिया स्तर की पाइप लाइन डाली गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष भर पाइप लाइन फूटती रहती है जो एस.एन. तिवारी और उसके मातहतों के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया होती है।

11 दिसंबर की सुबह किशनगंज से फूटी पाइप लाइन जिस तरह से फूटी उसके घटना स्थल पर टुकड़े को चौकोर आकार में देखकर लजता है। जैसे कि पानी चोरी के इरादे से आजू-बाजू के खेतों में सिंचाई करने के या अन्य मंतव्य से योजनाबद्ध तरीके से फोड़ी गई फोड़ने वाले के खेतों को पानी मिल गया, जोड़ने वाले हाथों को धन।

इंदौर। नर्मदा से इंदौर तक विछाई गई पाइप लाइन क्या खालिस सीमेंट के घटिया स्तर के पाइपों की है। जबकि सप्लायर से निविदा की शर्तों में कहा गया होगा कि भारतीय मानक स्तर की मान्य अंदर बाहर सीमेंट चढ़ी कच्चे ढलवां लोहे की पाइप लाइन आपूर्ति की जाए। हरामखोर जुनेजा ने समाचार पत्रों को वक्तव्य दिया कि वह 25 वर्ष का समय पूरा कर चुकी है तो महाभ्रष्ट गिद्ध एस.एन. तिवारी जो अनेकों वर्षों से यहां पर है कम से कम रु. 10 करोड़ से ज्यादा कहां से कमा कर लाया। इस भ्रष्ट के ऊपर लोकायुक्त का छापा भी पड़ चुका है, परन्तु वो लाइन अटैच भ्रष्ट लोकायुक्त के पुलिसिये अधिकारी वर्षों बाद भी उसकी चार्जशीट न्यायालय में नहीं लगा पाए और इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी.

अशोक मिश्रा सहायक यंत्री भी कब से वुंडली मारे बैठा है। मंत्रियों, अधिकारियों जो भोपाल या म.प्र. में कहीं भी बैठे होते हैं। यहां उनकी देख-रेख के परिणाम स्वरूप उनकी कृपापात्र ये भ्रष्ट भी वर्षों से कुंडली मारे इंदौर में ही जमा हैं।

इतने सारे गिद्धों और हरामखोरों के रहते अगर पाइप लाइन नहीं फूटेगी तो क्या खालिस वेतन से घर चलेगा, मौज-मस्ती, अय्याशी और नाम चलेगा फिर क्या यहां बैठने की कीमत मंत्री से सचिवों तक क्या वेतन से दी जाएगी।

जब-जब पाइप लाइन फूटती टूटे पाइप से ही तो पैसा ऊपर तक पहुंच पाता है और जेब में ही आता है। ऐसे कार्यों में कार्य प्रथम प्राथमिकता होती है। वर्ना जनता चिल्लाएगी तो जांच बैठ जाएगी विधानसभा गूंज उठेगी। इसलिए अनाप-शनाप पैसा खर्च दिखा कर झूठे बिल लगा कर लाखों रुपया हर वर्ष डकार लिया जाता है।

पुराने वाल्वों, पुराने स्टाक के पाइप व अन्य सामग्री का उपयोग कर कुछ गिने चुने ठेकेदारों के माध्यम से काम दिखाकर बाकी पैसा हजम, फिर खोदने, भराई करने में विभागीय नियमित कर्मचारियों जो वर्क चार्ज के मजदूर होते हैं से काम करवा कर आकस्मिक या ठेके पर दिखाकर मजदूरी का पैसा हजम। तीन ट्रक मुरम डाली या वहीं की मिट्टी पलटा कर भर दी गई। पर बिल तो ट्रकों की ढुलाई और भराई का ही लगेगा न इतना तो चलता है रु. 5-10 लाख का एक बार फूटने का बिल नहीं बना तो क्या पाइप लाइन फूटी।

आखिर जिस तरीके से वो खालिस सीमेंट का टुकड़ा अलग से दिख रहा था, उससे स्पष्ट होता है कि पूर्व नियोजित तरीके से पानी चोरी, खेतों की सिंचाई या विभागीय स्तर पर की गई फोड़ने की कार्यवाही, ताकि कैसे भी हो कमाई,

खालिस सीमेंट का पाइप ही ऐसे चटक सकता है यदि कच्चे लोहे का अंदर बाहर सीमेंट की पर्त चढ़ा पाइप होता तो ज़ो चटक ही गया ऐसे नहीं फूट सकता था। पहले दरारें बनती, दरारों से पानी बहता 4-6 महीने पानी बहने के बाद दिनों-दिन कमजोर होता फिर टुकड़े टूटते न कि बाकायदा चौकोर कटकर अलग गिरता।

यदि पाइप लाइन फूटने पर जांच बैठाई जाए तो मालूम पड़ेगा कि घटिया स्तर के जो पाइप लाइन बिछाई गई थी वो खालिस सीमेंट की है उसमें लोहा अंदर बिल्कुल भी नहीं है। न ही इतनी पाइप लाइन बनाने के लिए फेरो कांक्रीट बनाया गया है फिर क्या आई.एस.आई. मार्का थी। इतिहास की गर्त में जाएं तो 1976 में डाली गई पाइप लाइन अशोक मिश्रा और एस.एन. तिवारी जैसे इंजीनियरों द्वारा ही बनाई गई होगी तब ही बार-बार फूटती है। जब-जब फूटती है इन भ्रष्टो की किस्मत चेतती है।

सेना घटा कर सुरक्षा एजेंसियो की मौत को दावत

कश्मीर से सेना हटाने का निर्णय कितना घातक सिद्ध हो रहा है ये जनता आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ रही है। सेना घटाना भी विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा ही है। यूरोपीयन अमेरिका और ब्रिटेन चाहते हैं कि काश्मीर के हालात इतने बिगड़ जाएं ताकि अमेरिका का अफगानी स्तल और ईराक की तरह सुलह के बहाने

धड़ाधड़ भून रहे हैं, ये नपुसंक कांग्रेसी सतातधीश भोग, वसूली में मस्त हैं

अपने सैनिक वहां बसा कर दिल्ली पर कब्जा जमा कर भारतीय गुलामों की औलादों को पुनः गुलामों की तरह हांक सकें।

सोनिया ने अपने आप को शांति का मसीहा सिद्ध करने के लिए काश्मीर के बेकाबू हालातों को कोढ़ में सेना घटाकर खाज फैलाने का काम किया। सोनिया अटल की बराबरी करने पर तुली है, परन्तु वो अटलजी की पैर की जूती भी सिद्ध नहीं होगी ये वो भी जानती है। देश के आंतरिक हालात दिनोंदिन बिगड़ रहे हैं। संसद का कांग्रेस समर्थित गुंडा लालू यादव रामविलास पासवान को मारने दौड़ता है। उस पर इतने सारे प्रकरण होने के बाद भी वह मंत्री है। शंकराचार्य पर हत्या के आरोप लगाकर चूंकि सत्ता इन धूर्त, मक्कार, अय्याश लुटेरे भ्रष्ट जमाखोरी और कालाबाजारी करवा कर जनता को लूटने वाले कांग्रेसियों की है उसे जेल में सड़ाया जा रहा है।

भाजपा ने सत्ता का सुख सच्चे अर्थों में पहली बार देखा था, इसलिए वो इन कुकर्मियों के पापों पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकी अन्यथा उसने इन हरामखोर धूर्त, मक्कार गिद्धों को इनके कुकर्मों के लिए सजा दिलवा ही दी होती तो इन मूर्खों को और जनता को ये दिन नहीं देखने पड़ते।

भाजपा ने कश्मीर के हालात सुधारने और पूरे दक्षिण एशिया में संबंध सुधारने का जो कार्य किया था सोनिया और उसका कठपुतली प्रधानमंत्री शायद कभी नहीं कर पाएंगे। सेना घटाकर तो इन मूर्खों ने आतंकवादियों को खुला तांडव करने का मौका दे दिया वैसे भी काश्मीर का आतंकवाद नेहरू का बोया इंदिरा का पालापोसा राजीव ने बड़ा किया, जिसकी फसलें सेना को काटनी पड़ रही हैं। नेहरू की अय्याशी और मूर्खतापूर्ण कृत्यों ने चीन से हार की तो हफा देकर 62000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा करवा दिया। सन 1947, 1965 की पाकिस्तान से लड़ाई में भले ही पाकिस्तान न जीता हो, परन्तु मुंह की तो खानी पड़ी। इंदिरा ने बंगला देश बनवाया जो अब नासूर बन पूर्वी राज्यों में बह रहा है।

अटलजी ने शांति वार्ता की पहल की तो कारगिल का मुंह तोड़ जवाब भी दिया और समझा दिया कि कमजोर न समझें। मनमोहन ने चंद महीनों में ही ठंडों में जबकि आतंकवादी बर्फ बरसने की आड़ में घुस आते हैं। सेना हटाकर उनके घुसने के रास्ते खोल दिए। फिर ये ही घुसे हुए आतंक वादी फिर से जुलाई-अगस्त तक धड़ाधड़ हत्याएं करेंगे और सेना के हटते ही कभी सेना के ट्रकों पर, कभी सीमा सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले कर अभी तक 50 से ज्यादा जवानों और अधिकारियों को चिर निद्रा में सुला चुके हैं। आश्चर्य है कि न तो गृह मंत्री न प्रधानमंत्री और न रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कोई बयान तक इनकी मृत्यु पर जारी नहीं किया। सब मौज-मस्ती और सत्ता का सुख भोगते हुए चारों तरफ से वसूली में उलझे हुए हैं।

एक तरफ बेहताशा महंगाई जिसमें पेट्रोल की कीमतें, गैस सिलेंडर कीमतें 20 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अनुदान खत्म करने का कहकर शंकराचार्य और कश्मीर में बढ़ती हत्याओं से मीडिया और जनता का ध्यान बंटाकर अपने वसूली, भ्रष्टाचार के कुकर्मों में व्यस्त हो दोनों हाथ से शासन और जनता का धन उलीच रहे हैं।

इन सबके पीछे सोनिया को यूरोपीय षड्यंत्रकारियों अमेरिका और इंग्लैंड की सलाह पर जानबूझकर सेना घटाई ताकि वहां के हालात अमेरिका द्वारा प्रत्यारोपित ही हैं कि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामले को सुलझाया जाए, जिसे भाजपा सिरे से खारिज करती रही है। सोनिया के माध्यम से बिगड़े हुए हालातों को काबू करने केलिए अमेरिका का और इंग्लैंड अपनी सेनाएं कश्मीर में स्थापित कर न केवल कश्मीर को हड़प लें वरन वहां बैठकर पूरे दक्षिण एशिया पर

(शेष पेज 4 पर)

(पेज 2 का शेष)

बीएसएएल.....

कंपनी है वेतन तो देगी ही। पर निगम बन गया है पिछाड़ू लात मार कर भगा देगी ये नहीं समझ रहा इन मक्कारों को।

भ्रष्ट निगम ने जो पिछले वर्ष सिम आई थी आधी काउंटर से बेचकर आधी रु. 200 की सिम रु. 5-5 हजार तक में बिकवाई फिर निगम महाप्रबंधक ही क्या भोपाल में बैठा मुख्य महाप्रबंधक से लेकर दिल्ली में बैठा मुख्य प्रबंध संचालक भी इन कंपनियों के पटके झूठे नोटों के टुकड़ों की गंदगी खाकर ही जी रहे हों तो केवल आश्वासनों के पुलिंदे ही जनता को बांट सकते हैं। फिर नए कनेक्शनों के नाम पर भी लाइनमेन सुपर वाइजर तक कभी ड्राय वाटर नहीं, स्विचेसन नहीं कहकर लटका कर स्वयं ही उपभोक्ता को निजी कंपनियों के हाथों सौंप कर भारी कमीशन कमा रहे हैं। निःसंदेह जनता इस चुक चुकी अधबूढ़ी फौज पर अभी भरोसा कर सबसे पहले इनके पास ही जाती है। जो निजी कंपनियों के लालची विज्ञापनों में नहीं फंसती, परन्तु शूकरों की फौज प्रतिस्पर्धा में भी उपभोक्ता का अपमान कर पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली है।

(पेज 1 का शेष)

सोनिया का षड्यंत्र-देश की चहुंमुखी बर्बादी करेगा

लेवाली से जहां जनता जिसे फायदा मान रही, केन्द्रीय कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। इसके विपरीत विदेशी खरीद से बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर का बड़ा हिस्सा विदेशियों के हाथ में जा रहा है, जो भविष्य में भारतीय लाभ उत्पादक कंपनियों के प्रबंधन पर विदेशियोंके कब्जे से दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होगा।

शंकराचार्य की गिरफ्तारी और उच्च व सर्वोच्च न्यायालय की बार-बार जमानत याचिका ठुकराए जाने के पीछे इस धूर्त की चाल मूल रूप से 40 करोड़ हिन्दुओं की भावनाओं को आघात पहुंचाना, भाजपा और रा.स्व.सं. को नपुसंक सिद्ध कर ईसाइयत और ईसाई धर्म प्रचारकों को बढ़ाके देना है। देश के इतिहास में सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी महिला सिद्ध होगी। सोनिया सबसे भयानक ऐतिहासिक षड्यंत्रकारी महिला सिद्ध होगी, भारत के इतिहास में। सास स्व. इंदिरा गांधी और पति. स्व. राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में आतंकवादियों के रूप में भिंडरावाला और लिट्टे को पालने वालों जिसको बाद में यूरोपीय देशों जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और इंग्लैंड ने ही इन दोनों की हत्या की ताकि सोनिया के रास्ते के कांटे साफ हो सके और वो कांग्रेस की सूत्रधार बन देश को अपने तरीके से चलाकर पुनः विदेशियों का गुलाम बना सकें। जो अब हम सब देख रहे हैं। कि वो प्रधानमंत्री न रहकर भी प्रधानमंत्री से ज्यादा है कंधा भर मनमोहन का है। परन्तु नीतियां, कारगुजारियां, महंगाई, शंकराचार्य की गिरफ्तारी, फिर जमानत न देना, सेना हटाना या घटाना, शेयर मार्केट की बनावटी, विदेशी वित्तीय संस्थानों की इतने ऊंचे अंशों के भावों पर खरीद की तेजी, 4000 अरब डालर के कर्जे, काश्मीर में आतंकियों द्वारा सेना और सुरक्षा एजेंसियों के सैनिकों की थोक बंद हत्याएं, हत्यारों, षड्यंत्रकारियों को सत्ता में बिठाया जाना सब इस धूर्त के षड्यंत्र के हिस्से ही हैं। फिर सेना का मनोबल तोड़ने के लिए सेना के थोकबंद 5000 जवानों को एड्स की बीमारी बताकर सेना और देश को कमजोर बनाना भी इसी के इशारे पर हुआ है।

अर्जुन, कमल, सुनील दत्त, प्रणव मुखर्जी जैसे उसके चरण सेवकों को देश नहीं, अपनी जाति अपनी गौरव नहीं, सोनिया दिख रही है क्योंकि ये हरामखोर सत्ता के भूखे श्वान देश की खातिर नहीं वरन सत्ता सुख भोगने और अपनी जय-जयकार सुनने के लिए राष्ट्र और उसकी 10 करोड़ जनता को नीलाम कर रहे हैं और उसके षड्यंत्रों में शामिल होकर देश के नाम पर रु. 4000 अरब डालर का कर्जा लेकर डकार जाएंगे, परन्तु भुगतान आने वाली सरकारों को ही करना पड़ेगा। राष्ट्र कोष यदि विदेशी भीख और ऋण से ही भरना है तो लानत है। ऐसे सत्ताधीशों की करतूतों पर तो सड़क का आदमी जो भीख मांगकर ही क्यों न गुजारा कर रहा हो थूकना भी पसंद नहीं करेगा।

महंगाई जो कांग्रेस का पुराने शौक, लूट और वसूली का पुराना ऐतिहासिक हथकंडा है 7 महीने में ही 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। रु. 35 का पेट्रोल रु. 42 हो गया। रु. 280 का गैस सिलेंडर रु. 495 हो गया जो घोषणा पत्र इन हरामखोरों ने भाजपा के बारे में घोषित किया था उस स्तर पर ये हरामखोर पहुंच रहे हैं। वर्ष भर में ये मक्कार जमाखोरी, कालाबाजारी और कीमतें बढ़ाकर वहां पहंच जाएंगे। फिर ये कमीने गुण गाएंगे कि अनुदान खत्म कर दिया तो जनता को नोंच कर सड़ा मांस खाने वाले कांग्रेसी गिद्धों अगर अनुदान भी दे रहे थे तो क्या तुम्हारी अम्मा स्व. इंदिरा गांधी के लूट के खजाने से बांट रहे हो, है तो वह भी जनता का ही पैसा न, तुम कौनसा अहसान कर रहे हो।

कांग्रेस का 55वर्ष पुराना बोया हुआ नासूर है कश्मीर की समस्या अय्याश नेहरू ने अब्दुल्ला जो उसकी अवैध संतान थी को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाकर उसे संविधान की धारा 370 में विशेषाधिकार दे दिए गए। स्व. इंदिरा गांधी ने अपने लूट, भ्रष्टाचार को छिपाए रखने के लिए कश्मीरी समस्या को पाल पोस कर बड़ा हथियार थामने वाला आतंकियों की शरणगाह बना दिया। भाजपा ने अंतिम छह वर्षों में नियंत्रण में करने की कोशिश की तो षड्यंत्रकारी इस विदेशी एजेंट सोनिया सेना कम करवा कर पूरी छूट दे दी आतंकियों को सेना, सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को भून देने की। यह है इस कांग्रेसी षड्यंत्रकारी मक्कार की नीति कि अपने ही देश के सुरक्षा सैनिक व अधिकारी धड़ाधड़ भूने जा रहे हैं। इन मक्कारों से एक शब्द भी नहीं फूट रहा। कि ये उस पाकिस्तान की निंदा भी कर सके।

शंकराचार्य की गिरफ्तारी से लेकर जमानत न होने देने की प्रक्रिया सिद्ध कर रही जुओं के अड्डों रूपी न्यायिक प्रणाली जो सत्ता में न्यायालय उसके गुलाम भ्रष्ट स्टार न्यूज चैनल ने तो कह दिया कि शंकराचार्य ने हत्या करवाना ही स्वीकार कर लिया। अर्थात कुल मिलाकर हिन्दुों के इस धर्म गुरु को इतना विवश कर दो कि वो जीवन ही नहीं वरन मौत के लिए गिड़गिड़ाने लगें। नराधम पापी कांग्रेसियों तुम कब तक जनता का ध्यान बंटाओगे। कब तक हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर ईसाइयत फैलाने केलिए अपने ही हिन्दु भाईयों का दोहन और शोषण करोगे मुर्दों तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं। जो उस षड्यंत्रकारी धूर्त महिला के चरण रज माथे पर लगाकर धन्य हो रहे। न्यायालय तो कल भी बिके हुए थे आज भी सत्ता के गुलाम हैं क्योंकि वेतन तो तुम्हारे शासन का ही खाते हैं न।

क्रमशः

(पेज 4 का शेष)

मत्स्य विभाग.....

अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की थी।

संचालक, मस्त्य पालन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2002) और संग्रहित जानकारी (अगस्त एवं दिसंबर 2003) को प्रकट हुआ कि 3.06 करोड़ रुपए की उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त अप्रैल 1997 से मार्च 2003 तक की अवधि के लिए निगम/मत्स्य महासंघ से 3.32 करोड़ रुपए की एक और राशिदेय हो गई थी। जिसके विरुद्ध निगम/मत्स्य महासंघ से केवल 1.08 करोड़ रुपए (1997-98:32.50 लाख रुपए, 1999-2000:50 लाख रुपए तथा 2002-2003:25 लाख रुपए) ही वसूल किए गए। इस प्रकार लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के उपरांत भी मार्च 2003 तक रायल्टी की बकाया राशि बढ़कर 5.30 करोड़ रुपए तक हो गई।

इसका उल्लेख करने पर विभाग ने सूचित किया कि रायल्टी की दरों का पुनर्निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और सरकार के निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा है तथापि सरकार ने सूचित किया कि प्रकरण नीतिगत निर्णय से संबंधित है और अभी तक विचाराधीन है।

सरकार का उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि पुनर्निर्धारित दरें भविष्यगत दिनांक से ही प्रयुक्त होंगी और इस प्रकार सरकार 21 माहों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं में की गई परिकल्पना के अनुसार विगत प्रकरणों में दोष निवारक कार्यवाही करने में विफल रही।

भ्रष्ट वा. कर में भ्रष्टोन्नति समीति के कारनामे

पदोन्नति समिति को जितनी मोटी रिश्वत उतना मोटा काम

म.प्र. उद्योग मंत्री कैलाश चावला जैसे शूकर गंदगी चाटने के आदि हैं तो वित्त सचिव, सिरोही, विभागीय पदोन्नति समिति या वाणिज्यकर आयुक्त भी तो दो पैर की जमात के प्राणी हैं। यदि वाणिज्य कराधिकारी निरीक्षक, सहायकायुक्त, उपायुक्त लूटेगा और वसूली करेगा तभी तो ऊपर पहुंचाएगा। जो आर.के. सौनी वा. कर अधिकारी वृत्त 10 में था, जिसकी ढेरों शिकायतें थीं, जिसकी शिकायत साकलका ने भी की थी, परन्तु सूत्रों के अनुसार रु. 20 लाख में पदोन्नति समिति ने 27.02.2003 को सहायकायुक्त बना दिया जबकि यह पदोन्नति क्रम में बहुत पीछे था और भ्रष्टाचार के ढेरों मामले

पत्रकारों द्वारा लगातार इसके भ्रष्टाचार की कारगुजारियों के प्रकाशन से एक वर्ष तक इस गिद्ध को लूट की खुली छूट देकर 25-5-2004 को भ्रष्टोन्नति समिति ने अपने खिलाफ उठती आवाजों के मद्देनजर इसे पदोवनत भी कर दिया गया। साथ ही रिश्वत के मोटे पोटले को देखकर पुन: अनुशंसा भी कर दी गई। आर.के. सोनी ने पदोन्नत होने से पदोवनत होने तक 27-04-2003 से 27-5-2004 तक सागर में सहायक आयुक्त रहते हुए करीब रु. 5 करोड़ कमाए। अंदाज लगाने के लिए इस व्यक्ति का रु. 1.50 करोड़ का बंगला इंदौर में इसी बीच बना जो सागर मुख्यालय पर मात्र 10 दिन रहता हो वह हरामखोर क्या कार्य अंजाम दे पाता होगा। उसने अपने निर्धारित लक्ष्य 650 प्रकरण निपटाने के स्थान पर 955 प्रकरण निपटाए। प्रति प्रकरण रु. 10,000 का औसतन से रु. 95.50 लाख अकेले दमोह के डायमंड सीमेंट को रु. 58 लाख की टैक्स छूट देकर मुफ्त का सीमेंट रु. 25 लाख ऊपर से डकार लिए गए। पत्रकारों ने जब इसकी संपत्ति के बारे में पूछा तो आयुक्त ने जवाब दिया आर.के. सोनी से पूछ लो। पाठक स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि वाणिज्य कर में लूटमार कैसे चल रही है जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री गौर तक सबको अपनी गंदगी से सींच कर खाद पानी दे रही है।

शासन में भ्रष्टाचार का कैसा साम्राज्य जिसके सामने सारे नियम कायदे कानून सब पीछे धरे रह जाते हैं। सवाल अगर वाणिज्यकर का हो तो वहां सीधा खेल लूटो और लुटाओ। सब कुछ भूल जाओ। क्या ..... मुख्यमंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त सचिव, सचिव आयुक्त, पदोन्नति समिति सारे भुखेरे श्वानों की फौज जिसके मुंह में जितना मोटा टुकड़ा जाएगा वो उतनी ही कूं-कूं करता नजर आएगा। चाहे दिग्गी दानव हो या बाबू गौर मुख्यमंत्री सब कमाने आए हैं। वाणिज्य मंत्री नरेन्द्र नाहटा हो या कैलाश चावला, वित्त सचिव सिरोही हो या जुलानिया सब भ्रष्टाचार की गंदगी में लोट लगाने वालेशूकरों की लुटाने वालों के सामने दुम हिलाती है। इसे सिद्ध किया वाणिज्य कराधिकारी वृत्त 10 ने। इस भ्रष्ट पर व्यापारियों से पैसा खाकर उल्टी-सीधी छूट का लाभ दिया के सैंकड़ों प्रकरण इसके वरिष्ठ साकलकर ने ही शिकायत में दिए थे। इसके विपरीत सूत्रों के अनुसार इस बंदे ने षड्यंत्रों के अंतर्गत यहां से नीमच स्थानांतरण करवाया और वहां जाने विभागीय भ्रष्टोंन्नति समिति को सन 2002 से जनवरी 2003 तक रु. 20 लाख विभिन्न माध्यमो से पहुंचाकर 27-2-2003 को सहायक वाणिज्य कर आयुक्त सागर बना दिया गया। यहां पर बैठते ही इसे पुरानी वसूली और नया बैंक बैलेंस बनाना था। इसके विपरीत यह बंदा मुख्यालय में ही 15-20 दिन जमा रहता था, जिसके मार्च 2003 से मई 2004 तक के यात्रा भत्ते, होटलों के बिल जिसकी क्षतिपूर्ति इसने शासन से ली होगी, देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत इसने 650 प्रकरणों के निपटाने के लक्ष्य के विपरीत 955 प्रकरण निपटाए और एक आलीशान बंगला जिसकी कीमत रु. डेढ़ करोड़ होनी चाहिए जिसमें स्वीमिंग पुल अंदर संपूर्ण संगमरमर, अंगर 7 ए.सी., वाटर फिल्टर प्लांट तक लगा है बनवाया। सीमेंट मुफ्त की डायमंड सीमेंट फैक्ट्री से लेकर रु. 58 लाख की छूट दे दी। एक प्रकरण निपटाने में मरी गिरी हालत में रु. 10 हजार तो मिलते ही हैं जो बढ़कर लाखों और करोड़ों तक पहुंच सकती है। रु. 25 लाख डायमंड सीमेंट फैक्ट्री से डकारने की खबर है। जब इसकी संपत्ति के बारे में एक पत्रकार ने पत्र दिया तो भ्रष्ट आयुक्त ने जवाब दिया कि आर.के. सोनी से ही पूछ लो। अर्थात चोर से पूछो कि उसने कितने की चोरी की। अच्छा है कि थाने के टीआई नहीं थे भ्रष्टायुक्त। छाया चित्र में पहला सफेद बंगला स्कीम नं. 71 में बंगला 17 DC है जो स्कीम नं. 71 में पीछे की तरफ बना है। इसमें फव्वारा तक लगा है। एक सहायक आयुक्त स्तर का बंगला किसी करोड़पति के बंगले से तो कम नहीं। बंगला प्रीति सोनी माँ रामकली सर्राफ के नाम से है। जिसमें आईसीआई सीआई बैंक से ऋण लेना दिखाया है। आईसीआईसीआई बैंक ने प्रीति सोनी पत्नी आर.के. सोनी को रु. 1 करोड़ का ऋण तो नहीं दिया होगा। फिर प्रीति सोनी से वसूली में भुगतान की व्यवस्था क्या थी। इसके विपरीत सोनी जब इंदौर में वृत्त 10 का वाणिज्यकराधिकारी था तो वाणिज्य कर कालोनी के एक छोटे से क्वार्टर में रहता था। सहायक आयुक्त बनते ही करोड़ों का धन कहां से आ गया यह न केवल लोकायुक्त की वरन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के लिए भी जांच का प्रश्न है। नि:संदेह बैठी तो यहां भी भुखेरों की फ़ौज ही है इसको भी धन खिलाकर मामला ठंडा करवा दिया जाएगा।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि वाणिज्य कर की विभागीय पदोन्नति समिति वास्तविकता में भ्रष्टोन्नति समिति ही है, जो बिना गुण-दोषों के भ्रष्टों से भ्रष्टाचार की गंदगी कर भ्रष्टों को नियम विरुद्ध पदोन्नतियां कैसे और क्यों बांट रही है। स्वाभाविक है इसमें भी जो भुखेरे श्वानों की फौज बैठी है उसे मुख्यमंत्री और वित्त सचिव का संरक्षण प्राप्त होगा ही। तब ही तो भ्रष्टाचार की गंदगी में लोट लगाकर पदोन्नतियां और पकड़े जाने या जांच बैठने के डर से पदोन्नतियां बांटती रहती है जो कि आर.के. सोनी के मामले में हुआ उसे सवा वर्ष खूब लूटने का मौका देकर 25-5-04 को वापिस पदोवतन अवश्य किया, परन्तु चूंकि श्वानों के मुंह में टुकड़ा फंसा था उसे उसी दिन पदोन्नति देने की भी अनुशंसा कर डाली।

वि.प.स. का यह आदेश जिसका निर्णय 25-5-04 को हुआ था 27-5-04 को जारी हुआ, जिसकी पूरी सूचना आर.के. सोनी को पहुंचा दी गई थी। आर.के. सोनी ने दो दिन में जो प्रकरण इसके पास निराकरण के लिए लंबित थे आनन-फानन लाखों रुपए लेकर समायोजित कर दिए। भ्रष्ट आर.के. सोनी अय्याश होने के साथ ही जुआ खेलने काभी भारी शौकीन है। वैसे जुआ खेलने और अय्यासी का शौकीन तो यहां सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर उपायुक्त तक होते हैं, जिसमें आर.सी. पालीवाल और एस.एल. वर्मा की अय्याशी के बारे में तो पहले भी समय माया ने समाचार प्रकाशित किए हैं। फिर भ्रष्टाचार का धन ही है जो सारे कुकर्मों को करने की प्रेरणा देता है और उत्प्रेरक बन मस्तिष्क को धन के उपयोग के बहाने अय्याशी, जुआ और जिंदगी में हर प्रकार के दांव खेलने क्या विभागीय पदोन्नति समिति, जांच अधिकारी, स्थानांतरण सबको खरीदने बेचने के खेल खिलवाता है।

जब वृत्त 10 का वाणिज्य कर अधिकारी था तब अपर आयुक्त साकलकर ने 200 पेज की इसके भ्रष्टाचार पूर्ण कृत्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो धन के ढेर में दब गई। सूत्रों के अनुसार मई-जून 04 में अतिरिक्त आयुक्त गुप्ता जो पूर्व में सागर जिलाधीश थे यहां बैठाए गए थे। इस हरामखोर की जांच के लिए परन्तु आर.के. सोनी ने लोगों से कहा बताते हैं कि जब मैं सागर में सहायक आयुक्त था तब ही गुप्ता वहां जिलाधीश थे। हमारे रोटी-वोटी के संबंध रहे हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं मुझे। कुल मिलाकर अहित नहीं कर सकते मेरा।

वैसे भी वाणिज्य कर आयुक्त से लेकर चपरासी तक सब अवैध वसूली के सिद्धहस्त हैं। सबका एक ही कहना है कौन ईमानदार की औलाद है तो किसी की जांच करने, पूछताछ करने की क्या औकात है। फिर पत्रकारों की क्या औकात बख्स सारे सब के सब 100-50 में बिकते हैं। रि 90 प्रतिशत पत्रकार जो यहां श्वानों की तरह मंडराया करते हैं कलम पकड़ना नहीं जानते अखबार निकालना तो दूर की कौड़ी है तो वो क्या कर सकते हैं।

मत्स्य विभाग में रायल्टी में घोटाला

म.प्र. मत्स्य विभाग में पूरे प्रदेश में तालाबों, बांधों में मछली उत्पादन, मछली बीज उत्पादन में करोड़ों का हेर-फेर किया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन में रायल्टी वसूली कर वहां कार्यरत जिलाधिकारी और निरीक्षक ही गांवों से बीज बांटने, बेचने और रायल्टी का पैसा डकार रहे हैं, जो करोड़ों रुपयों में है। इस बारे में नियंत्रक महालेखाकार ने भी अपनी विधानसभा में प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी की है।

म.प्र. शासन के कुछ विभाग शासन का कर्मचारियों और अधिकारियों पर करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, परन्तु शून्य ही रहा है। इसमें ही एक विभाग है म.प्र. मत्स्य विभाग, जिसका काम होता है मछली बीज का उत्पादन और उस बीज को उसके अंतर्गत तालाबों, बांधों में बीज डालकर मत्स्य पालन छोटे तालाबों जो गांवों की पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, पट्टे पर देकर स्त्रोत उपलब्ध करवाना, इसके साथ म.प्र. जल संसाधन विभाग जो पूर्व में सिंचाई विबाग के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा निर्मित तालाबों, स्टापडेमों, बड़े बांधों से वर्ष भर मछली उत्पादन प्राप्त करना। ग्रामीणों को तालाब विकसित करने के लिए शासन 20 से 25 प्रतिशत तक अनुदान भी देता है। अगर ग्रामीण अपने ही खेतों में तालाब बनाता है और मछली उत्पादन करते हैं तो।

इस विभाग में मछली के बीजों के विकसित करने और उन्हें तालाबों में डालने में भी उसके बाद रायल्टी पर दिए तालाबों की रायल्टी वसूलने में प्रदेश स्तर पर करोड़ों का घोटाला हो जाता है। इंदौर में बैठा संयुक्त संचालक मत्स्य पेंटर, धार में बैठा सिंग जो अभी प्रभारी है, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम में बैठे सभी जिलाधिकारियों से लेकर निरीक्षक तक रायल्टी के धन को किसानों और उत्पादकों से वसूल कर स्वयं ही डकार रहे हैं। यह राशि करोड़ों रुपए में होती है, जिसकी वसूली बराबर की जा रही है, परन्तु शासन और पंचायत के अंतर्गत आने वाले तालाबों की पंचायत या अन्य शासकीय विभागों में जमा नहीं हो रही। धार के सिंग की कार्यालयीन सूत्रों के अनुसार यह मक्कार लाखों रुपए प्रति वर्ष शासन के रायल्टी के माध्यम से मछली बीज उत्पादन में जो संख्या ये बताते हैं लाखों में उसका 50 प्रतिशत से ज्यादा बीज ये तालाबों में नहीं छोड़ते और निजी तालाब वालों को बेचकर पैसा डकार लिया जाता है। म.प्र. के मत्स्य विभाग के संबंध में भारत के महा नियंत्रक लेखाकार का विधानसभा में सन 2003 का प्रतिवेदन भी प्रतिकूल टिप्पणी कर चुका है जो निम्नानुसार है। पृष्ठ क्र. 254

उपरोक्त टिप्पणी यह सिद्ध करती है कि शासन को म.प्र. के वृहत व लघु बांधों, वृहद लघु तालाबों से, नहरों से लगभग 5000 टन मछली उत्पादन प्राप्त हो रही है, जिससे अकेले बरगी जबलपुर, गांधी सागर बांध मंदसौर, इंदिरा सागर और नर्मदा सागर जैसे बांधों से प्रति वर्ष लगभग 4000 टन मछली प्राप्त हो रही है जिस पर म.प्र. शासन ही बीज डलवाकर मत्स्य उत्पादन करवाता है, परन्तु मत्स्य विभाग निगम को बंद कर वहां मत्स्य महासंघ बैठा दिए गए जो सारा पैसा रु. 50 प्रति किलो के हिसाब से 200 करोड़ रुपए बाले-बाले स्वयं ही डकार रहे हैं। 1000 टन मछली छोटे बांधों जैसे माही, जोबट जैसे 200 बांधों, 20,000 तालाबों जो पूरे प्रदेश में फैले हैं, से लगभग 1 हजार टन मछली जो प्राप्त हो रही है उससे किसान, सरपंच स्थानीय मत्स्य विभाग के निरीक्षकों से लेकर जिला अधिकारी तक हजम कर रहे हैं। रु. 50 प्रति किलो औसतन दर है थोक भाव में जबकि रोहू और तेल वाली मछली की दरें रु. 100 से 200 प्रति किलो तक बाजार में बिक रही है। नि:संदेह मछली चोरों का गिरोह भी स्वयं ही मत्स्य महासंघ का ही है फिर मछली लघु वृहत तालाबों के अतिरिक्त नर्मदा, चंबल, कालीसिंध जैसी नदियों से भी निकाली व बेची जाती है वह भी लगभग 500 टन वार्षिक से ज्यादा है।

शासकीय निष्क्रियता से ही शासन के अधिकारी और कर्मचारी ही शासन को घाटा दे रहे हैं।

(भारत के महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। पृष्ठ-154)

4.5.2 मछली पकड़ने पर रायल्टी वसूल न करना

लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं कार्यान्वित नहीं की गई और मत्स्य महासंघ की वसूली योग्य रायल्टी में मार्च 2003 तक 5.30 करोड़ रुपए तक वृद्धि हो गई।

भूतपूर्व मध्यप्रदेश राज्य मस्त्य विकास निगम (निगम) द्वारा मछली पकड़ने पर मत्स्य पालन विभाग को रायल्टी का भुगतान करना अपेक्षित था। निगम 1 अगस्त 1999 से भंग कर दिया गया जब उसकी परिसंपत्तियां एवं देयताएं नवसृजित मत्स्य महासंघ (सकारी) मर्यादित मत्स्य सहकारिता के महासंघ (पंजीकृत सहकारी समिति) को हस्तांतरित कर दी गई। उसके बाद से संघ द्वारा बकाया सहित सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर रायल्टी का भुगतान करना अनिवार्य है।

मार्च 1997 को समाप्य वर्ष के प्रतिवेदन (क्रमांक 4 सिविल) की कंडिका 3.15 में मार्च 1997 तक 3.06 करोड़ रुपए की रायल्टी की बकाया राशि का उल्लेख किया गयाथा। लोक लेखा समिति ने अपने 198वें प्रतिवेदन (अप्रैल 2002) में राज्य के हित में मछली पकड़ने केलिए एक नीति के निर्माण और रायल्टी वसूल न करने हेतु उत्तरदायी

(शेष पेज 3 पर)

(पेज 3 का शेष)

सेना घटाकर.....

दादागिरी कर सके क्योकि वहां सेना केवल भारत वरन चीन, पाकिस्तान, रूस पर भी चौकसी, जासूसी और नियंत्रण स्थापित किया जा सके। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ये मानकर ही चलते हैं कि रात हजारों वर्षों से गुलामों का देश रहा है और वर्तमान गुलामों की औलादों पर यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो ये हर क्षेत्र में पैर पसार लेंगे। यही इच्छा पूरे यूरोप और इटली के पोप की भी है। कि हर तरह से भारत को काबू में करके रखा जाए। कश्मीर में सेना घटाना इस सोची समझी दूरगामी रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

विश्वविद्यालय बन चुके हैं जालसाजी और अय्याशी के अड्डे

पूर्व कुलपति अशर्फी लाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र जालसाजों द्वारा रचा गया जिसमें कांग्रेसी राज्यपाल जाख़ड़ भी शामिल

कांग्रेसी राज्यपाल एवं कुलाधिपति

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सुधाकर भारती जैसे जालसाज वर्षों से कैसे और क्यों जमे हैं। फिर भ्रष्टों हरामखोरों की कितनी हिम्मत हो गई कि वो अपने साथियों को ही अपनी जालसाजियां दबाने के लिए हस्ताक्षर करवाने के लिए चांटे मारने लगे। वैसे भी शासकीय निजी महाविद्यालयों में वर्षों से जमे प्राध्यापकब शिक्षक कम युवा पीढ़ी को बहका कर अपनी कमाई और स्वार्थों के लिए पूरे प्रदेश के अधिकांश शासकीय स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालय भी गिरोहों के मुखिया रूपी गुंडे बदमाशों के अड्डे बन चुके हैं, जिसको वर्तमान में पूर्व का भ्रष्ट और वर्तमान का राज्यपाल जाखड़ और संरक्षण दे रही है।

भ्रष्ट प्राचार्य श्रीवास्तव
शा. दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

इन्हीं गुंडे बदमाशों रूपी भ्रष्ट प्राध्यापकों, डीनों के साथ कांग्रेसी नेताओं की साजिश का परिणाम था अशर्फी लाल शर्मा को हटाया जाना। वैसे भी इंदौर विश्व विद्यालय के अधिकांश पुरुष प्राध्यापक जहां छात्राओं का वही महिला शिक्षिकाएं अपने छात्रों का भरपूर यौन शोषण करते हैं न नुकुर करने पर सीधे ही परीक्षण परिणाम बिगाड़ दिए जाते हैं। ये हालात न केवल होल्कर विज्ञान महाविद्यालय वरन कला एवं वाणिज्य, विधि, प्रोफेशनल अध्ययन संस्थान, पूरे विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान तक्षशिला परिसर खंडवा मार्ग के साथ ही म.गा. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय तक के हैं। जहां हर बात का खुलकर पैसा खाया जाता है, प्रवेश परीक्षाओं के नाम से लेकर प्रायोगिक परीक्षाओं, परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने आदि तक सारा खेल पैसों से शुरू होकर पैसे पर ही समाप्त होता है।

शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात तो बहुत दूर पुरानी हो चुकी है। शिक्षा संस्थान मुख्य रूप से विश्वविद्यालय जिसमें देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, बरकत उल्ला बोपाल, जीवाजी ग्वालियर, रानी दुर्गावती जबलपुर, रीवा ग्रामोदय चित्रकूट, भोज (मुक्त) भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता वि.वि. भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. भोपाल अधिकांश विश्वविद्यालय और सभी शासकीय इनसे जुड़े महाविद्यालय, माफियाओं, गुडों, राजनैतिक दलों के नेताओं की जालसाजियों, भ्रष्टाचारों और अय्याशी के अड्डे बन चुके हैं। दूसरी तरफ निजी माविद्यालयों, गुडों और नेताओं की अय्याशियों, अवैध वसूलियों, लूट केलिए बनाए गए अड्डे ही हैं। जिसमें म.प्र. शासन के अधिकांश सचिव इन सबके संरक्षक, सहयोगी और अय्याशी लूट के सह भागी हैं।

वर्तमान प्रदेश के हालात ये हैं कि शिशु वर्ग की कक्षाओं से लेकर चिकित्सा, अभियांत्रिकीय, प्रबंधन, कम्प्यूटर, शिक्षा, औषधि विज्ञान तक के महाविद्यालयों में भी प्रवेश से लेकर डिग्री लेकर निकलने तक कदम-कदम पर छात्र-छात्राओं को लूट, भ्रष्टाचार, जालसाजियों और यौन शोषण का शिकार होना, बनना पड़ता है। नि:संदेह इस सबके पीछे कांग्रेसी नीतियों का भ्रष्टाचार, जालसाजियां रही हैं। जाते-जाते दिग्गी दानव ने अकेले भोपाल में ही तीन फर्जी विश्व विद्यालयों जिसमें भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, पं. माखनलाल चतुर्वेदी और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालयों की स्थापना करना भी था। उस हरामखोर का तो बस नहीं चला वर्ना हर शहर में एक निजी विश्व विद्यालय होता। जैसा कि छत्तीसगढ़ में जोगी ने किया था। उसके कार्यकाल में रायपुर और बिलासपुर में विश्वविद्यालय होने के बाद भी 39 निजी विश्वविद्यालय और खोल दिए गए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को ही लें तो पिछले 5 वर्षों का इतिहास उठाकर देखें तो महा मक्कार कुलपति भरत छपरवाल बी भारी जालसाजियां की। छात्राओं के यौन शोषण के किस्से तो विश्वविद्यालय का चप्पा सुनाता है। प्रवेश परीक्षाओं और प्रवेश सेलेकर प्रायोगिक परीक्षाओं में सैद्धांतिक परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने, पेपर लीक करवाने, प्रश्न बांटने तक में यहां हर प्रकार की जालसाजियों का अंबार है। अशर्फी लाल शर्मा भाजपा समर्थक माने जाते थे तो भरत छपरवाल कांग्रेस समर्थक, चड्ढा भी कांग्रेसी है। सुधाकर भारती के कुकर्मों की सूची और उनके कार्यकाल की धूर्तताओं, वसूलियों और जालसाजियों पर तो पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। नि:संदेह राजनैतिक पार्टियां इस युवा वर्ग के दम पर ही अपनी राजनीति की रोटियां सेंकती हैं। राजनैतिक छात्र नेता चाहे वो अभाविप, भारछासं कोई भी हो सब बिना पढ़े-लिखे नेतागिरी के दम पर शैक्षणिक संस्थानों की सारी सुख-सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपने पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण कर अपना राजनैतिक भविष्य बनाने की तैयारी में यही से लग जाते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी इन सबसे दूर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर यहां से चुपचाप खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझते हैं।

दे.अ.वि.वि. परिसर में देवता के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पिटाई खुराना द्वारा किया जाना मामले की गंभीरता, जालसाजी गुंडागर्दी और माफियाओं के सरगनाओं के कब्जे की पुष्टि करता है। वर्तमान कुलपति चड्ढा की नियुक्ति बलराम जाखड़ जो कांग्रेसी पहले हैं राज्यपाल बाद में स्वाभाविक है कांग्रेस वाद की कठपुतली रहेंगे। एक झूठी शिकायत पर भी या तो हस्ताक्षर करो वर्ना नीच और कुत्सित प्रकृति का खुराना उठा कर बाहर फेंक देंगे यह जब प्राध्यापक स्तर का व्यक्ति कह रहा है तो विश्व विद्यालय परिसर में पढ़ाई क्या और कैसी होगी इसका अंदाज लगाया जा सकता है।

इसके उदाहरण में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के निष्कर्षों को लें तो यहां पर बैठा धूर्त मक्कार प्राचार्य डॉ. बी.एन. श्रीवास्तव और उसका चेला डॉ. देशराज जैन कैसी जालसाजियां कर रहे हैं, जिसके विरोध में छात्रों को हड़ताल तक करनी पड़ी। छात्रों ने बताया कि स्नातकोत्तर कक्षाओं का परीक्षण 2003-04 में शून्य रहा। स्नातक पाठ्यक्रम का मात्र 33 प्रतिशत इसके पीछे देशराज जैन की चाल थी पैसा दो और पास हो, स्नातक कक्षाओं में 33 प्रतिशत परीक्षा परिणाम के पीछे नगर में खुले दो महाविद्यालयों गांधीनगर और राऊ के निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को लाभांवित करना था। डॉ. श्रीवास्तव और डॉ. देशराज जैन की चाल ये है कि कम से कम परीक्षा परिणाम दो ताकि लाखों रुपए लेकर बाहरी छात्रों को द्वितीय तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सके। जब इस धूर्त डॉ. श्रवास्तव से पूछा गया कि परिणाम शून्य कैसे आया तो बड़ी मक्कारीपूर्ण अंदाज में बोला मैं क्या कर सकता हूं विश्वविद्यालय से पूछिये

(शेष पेज 2 पर)

चौपाल से खरीदी का अधिकार क्यों?

भ्रष्ट गौर ने रु. 1 अरब लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों प्रदेश नीलाम किया

भुखेरे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने रु. 1 अरब लेकर आईटीसी को गांवों की चौपालों से माल खरीदने का अधिकार देकर प्रदेश के व्यापारियों और किसानों का भविष्य गिरवी कर दिया। जैसा कि व्यापारियों ने हड़ताल के दौरान बताया कि बिना 1 अरब रुपए के लेन-देन बाबूलाल गौर प्रदेश के किसान और व्यापारियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों नहीं बेच सकते थे। कया हुआ भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी और स्वयं सेवक संघ को। क्या सब भुखेरे श्वानों की फौज बहुराष्ट्रीय कंपनी से मिली मोटी रकम मुंह में फंसा कर सो रहे हैं। यदि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चौपाल से खरीदी का अधिकार मिल सकता है तो प्रदेश के सभी अन्य लाइसेंस चाहने वाले व्यापारियों को क्यों नहीं? या फिर बहुराष्ट्रीय कभी मंडी का शुल्क अदा कर मंडी में से ही खरीदी क्यों नहीं करती।

भोपाल। प्रदेश सरकार जन हितैषी कार्य कर रही है इसके सैंकड़ों उदाहरण प्रतिदिन समाचार पत्रों के आधे-अधूरे समाचारों में मिल ही जाते हैं। आए दिन जनता, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र हड़ताल पर चले जाते हैं। आखिर क्यों? ठीक है आप अपने वादे जो जनता से किए थे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुराने पापों यानी जो कुकर्म किए थे उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इसके विपरीत ये मुख्य मंत्री भी दिग्गी दानव के पद चिन्हों पर चलकर वैसे ही लूटखसोट में जुट गए हैं। यही कारण है चारों तरफ से उसके भ्रष्टाचार पर अंगुलियां उठने लगी हैं। हाल में जो ताजा भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने ाया है उसमें इस हरामकोर राष्ट्रीय कंपनी इंडियन टौबेको जिसकी 49 प्रतिशत इसकी मूल कंपनी ब्रिटिश टौबेको के पास है। म.प्र. के गांवों के चौपालों से सीधी खरीदी करेगी, जिससे न केवल म.प्र. शासन को मंडी शुल्क के रूप में मिलने वाली 2 प्रतिशत तो डूबेगा ही साथ में ये किसानों के उनके गांवों में रोककर ही किसानों से अपनी शर्तों पर माल की खरीदी कर लेगी। किसानों का शोषण बिना शासन की नजरों में आए ही गांवों में करने का इस धूर्त ने प्रबंध कर दिया है। स्वाभाविक है यहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय गुंडों का उपयोग कर औने-पौने भावों पर ही बिना भाव खुले ही अरबों रुपए का दलहन, तिलहन, अनाज व अन्य व्यवसायिक फसलें खरीद कर चहुंदिशि कर सकेगी।

यदि बहुराष्ट्रीय कंपनी को खरीदी करनी है तो जिलों की मंडियों में लाइसेंस लेकर मंडियों से ही खरीदी क्यों नहीं करना चाहती क्योंकि उन हरामखोरों को मंडियो की खरीदी से प्रतिस्पर्धात्मक दरों का ही भुगतान करना पड़ेगा और यहां मन चाहे तरीकों से औने-पौने भावों में नापचौल में बेईमानी नहीं कर पाएंगे। फिर यहां मंडी शुल्क भी देना होगा। तीसरा यहां कुल खरीदी का रिकार्ड भी रखा जाएगा। इसी तथ्य को लेकर मंडी व्यापारियों ने हड़ताल की है। प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कप्तान सिंह सोलंकी और कृषि मंत्री का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रदेश में गांवों की चौपाल से खरीदी करने का अधिकार इसलिए दिया गया कि चौपालों पर किसानों को ज्यादा कीमतों का भुगतान होगा जो इन हरामखोरों की पूर्णत: जालसाजी पूर्ण हरकत है। इसके संबंध में प्रदेश के व्यापारियों का कहना है कि करीब रु. 1 अरब के लेन-देन के बाद ही यह संभव हुआ है। यदि ये धूर्त चौपालों की खरीदी का अधिकार विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं और हमें अधिकार नहीं चौपाल से खरीदी का तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्यों?

इससे भाजपा के किसानों के कितने हित पूरे होंगे ये सब जानते हैं साथ ही ये किसानों की सरकार बताने वाली सरकार किसानों को रबी की फसल पर तो बिजली दे नहीं पा रही। फिर किसान डीजल इंजिन से पानी निकालकर कुओं से खेतों की सिंचाई कर रहा है। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों का हित देखने के लिए नहीं आ रही और चौपालों से खरीदी की जालसाजी किसानों से अच्छी क्वालिटी का माल खरीद कर अपना पेट बड़ा करने और लूट करने के लिए है न कि देश, प्रदेश और किसानों का भला करने के लिए।

इसमें भ्रष्ट बाबूलाल गौर की लेन-देन करने के बाद जारी चौपाल खरीदी के लायसेंस से जालसाजी के इरादे साफ प्रगट होते हैं।

मानव अधिकार आयोग क्या करवा पा रहा है?

शासकीय लापरवाही, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही का शिकार

मानव अधिकार संस्थाओं के नाम पर फर्जी व कुकर्मियों की बाढ़ विश्व में चारों तरफ मानवाधिकार उल्लंघन की बात की जा रही है, परन्तु मानवाधिकारों की बात करते हैं। जैसे अमेरिका दूसरों पर खास तौर पर भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है, परन्तु स्वयं शंकर प्रजाति के मानवों का ये देश दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में सेना में रखकर क्या नहीं कर रहा।

भारतीय मानवाधिकार आयोग में ऊपर से नीचे तक बैठे वे ही लोग हैं जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और भारी भ्रष्ट थे। यही कारण है कि मानवाधिकार आयोग व संगठन भ्रष्ट, कुकर्मी और अपराधियों के गिरोह बन चुके हैं, जिनका उ-ेश्य जन साधारण को न्याय दिलाने की अपेक्षा खुद कमाई करना, अपने भ्रष्टाचारों का ढाकना और अधिकार संपन्न होने के कारण अपने स्वार्थों की पूर्ति करना।

पूरे विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले आए दिन अखबारों की और टीवी समाचारों की सुर्खियों में छाए रहते हैं। विश्व का गुंडा अमेरिका उसके राष्ट्रपति और वहां एमनेस्टी इंटरनेशनल आए दिन दक्षिण एशिया के देशों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं। पर स्वयं विश्व का ये गुंडा वर्तमान में उसकी 80 से ज्यादा देशों में पड़ी सेनाएं चाहे फिर वो जापान, जर्मनी हो या अफगानिस्तान और ईराक में क्या कर रही है। ये दुनिया ने अच्छी तरह दूरदर्शन समाचार शृखंलाओं पर विश्व व्यापी अंतरराष्ट्रीय सूचना जाल की साइटों पर देखा है जो सामने नहीं आया। समय माया के श्री अजमेरा ने छठी इंद्रिय के केन्द्रित ध्यान से देखा जहां अफगानिस्तान और ईराक में अमेरिकी व सहयोगी देशों की सेनाएं 10-12 वर्ष की लड़कियों से लेकर अवयस्क और वयस्क महिलाओं के साथ कैसे पकड़-पकड़कर किसी भी बहाने सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। पुरुषों को मात्र इस आशंका के चलते ही कि वे अमेरिकी सेना विरोधी हैं, गिरफ्तार कर कारावासों में भयानक यातनाएं दी जा रही हैं। वहां मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो रहा।

मानवाधिकार उल्लंघन एशियाई देशों में मुख्य रूप से भारत के काश्मीर में हो रहा है। जहां आतंकवादियों के विरुद्ध सैन्य बलों का प्रयोग किया जाता है। यह आरोप शुरू से मानवाधिकारों के विचार और उसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय धारा में आने के बाद से शुरू से लगते रहे हैं। या अमेरिका और उसकी वित्तीय सहायता प्राप्त एमनेस्टी इंटरनेशनल लगाती रही है। भारतीय सरकारों पर ताकि उसके वित्तीय आर्थिक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के आई.एस. आई. के द्वारा संचालित आतंकवादियों को खुले में भारत में आतंक फैलाने की छूट मिल सके। जो पूर्णत: अमेरिकी दादागिरी का बदतमीजी पूर्ण भारत की सार्वभौमिकता के प्रति खुला धूर्ततापूर्ण कृत्य है। भारत शासन चाहे तो अमेरिका को उल्टा ही फटकार सकता है, परन्तु केन्द्रीय शासन में बैठे हर महाभ्रष्ट को उसकी तरफ से मिलती भीख का धन मिलना बंद हो जाएगा का अंदेशा रहता है। इसलिए कांग्रेसी और भाजपाई सरकारें चुप्पी साध लेती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग कार्यशील है और प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर बैठे आयोगों में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो पूर्व से ही महा भ्रष्ट और शासकीय अधिकारियों और मंत्रियों के तलुवे चाट कर नियम कानूनों को बलाए ताक रखकर अपने स्वार्थों की आपूर्ति में आकंठ लिप्त रहते हैं। ऐसे हरामखोर धूर्त मक्कारों से न्याय की उम्मीद करना तो एकदम निरर्थक और मूर्खतापूर्ण ही है। इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कमजोरी ये है कि सारे कर्मचारी या अधिकारी एक तो ऐसे आयोगों में कार्य करने के लिए शासकीय वित्तीय सहायता पर निर्भर करते हैं दूसरा उनकी राजीमर्जी सरकार से ही उन्हें अनुदान मिलता है अगर वो शासकीय भ्रष्टाचार मंत्रियों और शासन में बैठे अधिकारियों के मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करेंगे और त्वरित निर्णय देंगे तो उन्हें वित्तीय सहायता और वहां बैठे अधिकारियों को वेतन भत्तों के साथ दूसरी सुविधा में मिलना बंद हो जाएंगी इसलिए सच्चाधीशों के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही सत्ता पलट तक स्थगित रखनी पडती है जिससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता।

तीसरा मानवाधिकार आयोग की कार्यशैली भी वही भ्रष्ट मक्कार और काम को टालने की प्रवृत्ति वाले न्यायाधीशों और कर्मचारियों से ही भरी है, जो कार्यों को नि:स्वार्थ भाव से नहीं अपने हितों के अनुकूल तरीकों से ही करते हैं। इसलि पीड़ितों को न्याय और शक्ति संपन्न पदाधिकारियों को अधिकारियों या कर्मचारियों को उनके किए कुकर्मों की सजा मिलने या आरोप लगाने में भी वर्षों गुजर जाते हैं। पीड़ित अपनी व्यथा लेकर शिकायत करने से ही संतुष्ट होकर चुप होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर ये भी जानबूझकर कानूनों के मकड़जाल में उलझाकर पीड़ितों को शोषित करके मजा देते हैं। चौथा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सबसे ज्यादा पुलिस के विरुद्ध ही पूरे देश में लगाए जाते हैं, परन्तु वो सब भ्रष्ट राजनीर्तिज्ञों की गोदी में बैठकर मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों से संबंध स्थापित कर मामले को रफा-दफा करवाने में सफल रहते ह पांचवा मानवाधिकार आयोग को सबसे महत्वपूर्ण होता है अधिकार संपन्नता, वह आयोग है मात्र। कोई न्यायालयीन संवैधानिक न्यायपालिका का हिस्सा नहीं वह किसी की जांच कर सकता है। दोषी पाए जाने पर उसे भी न्यायालयीन प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा फिर न्यायालयीन प्रक्रिया से भी भूतपूर्व राष्ट्रपति के शब्दों में जुए के अड्डे हैं। न्याय के मंदिर नहीं जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना ही न्याय को पाने के अवसर मिलेंगे। स्वाभाविक है कि अधिकार और शक्ति संपन्न बड़ा दांव खेलेगा और कानूनी प्रक्रिया में लीपा-पोती करवा कर पैसे खिलाएगा और तीराखों पर तारीखें बढ़वाकर बचता रहेगा।

(पेज 1 का शेष)

एड्स.....

और महिलाओं को नपुसंक और बांझ बना दिया जाए। ताकि यूरोपियन षड्यंत्रकारियों को पुन: भारतीय अस्मिता का यौन शोषण करने का अवसर उपलब्ध हो सके। पूरा आसाम उत्तरी भारत के राज्यों में चाय बागानों में पैदा होने वाली पिछले दो सौ वर्षों में पूरी कौम गोरी इसाई ऐसे ही नहीं बन गई वो सारे अंग्रेजों की संकर प्रजाति है।

भारतीय आयुर्वेद जो हमारे चार वेदों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मानव जीवन के सूक्ष्मतम अंशों और स्वास्थ्य रहने की चिकित्सा पद्धतियों का विस्तृत अध्ययन है। उसमें तो ऐसी किसी बीमारी का वर्णन कहीं नहीं है। फिर भगवान धनवंतरि रचित आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सुश्रुत संहिता, भृगु रचितज्योतिष शास्त्रों, चिकित्सा पद्धति, चरक संहिता जैसे ग्रंथों में सुजाक, गर्मी, श्वेत प्रदर जिसे हम सिफलिस गनोरिया, ल्युकोरिया कहते हैं में कैंसर आबुर्द जिसके 12 प्रकारों जिस पर वर्तमान में मात्र अनुसंधान ही चल रहे हैं को चिकित्सा विश्लेषणों को शताब्दियों पूर्व विस्तृत रूप से वर्णित कर दिया था कहीं शरीर की यौन जनित बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता के नष्ट होने जैसी किसी बीमारी का उल्लेख नहीं।

वही हाल यूनानी और होम्योपैथिक में भी है कि इस सबमें भी सिफलिस गनोरिया जैसी बीमारियों की चिकित्सा के उल्लेख हैं उनकी चिकित्सा के विस्तृत विवरण हैं। होम्योपैथिक कितनी सूक्ष्म व्याख्या करता है मानव शरीर और उसके विकारों की ये साधारण व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर है, परन्तु उसमें भी कोई ऐसी बीमारी नहीं जबकि ये स्थिति संयुक्त रूप से अनेकों विपरीत श्रेणी के रोगों में उत्पन्न हो जाती है जेसे मधुमेह के रोगी को पीलिया हो जाए यकृत कमज़ोर हो जाए तो शकर नियंत्रण करोगे तो पीलिया बढ़ेगा, ऐसी अवस्था में ऊपर से कोई तीसरा चौथा रोग और आक्रमण कर दे तो स्वाभाविक है कि डाक्टर असहाय हो जाते हैं, क्योकि इलाज कैसे करें एक को ठीक करें तो दूसरा बिगड़ता है तो हरामखोर धूर्त डाक्टरों का टोला एड्स घोषित करके बच लेता है।

जबकि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाया 10 पैसे का कंडोम रु. 10 में बेचने पर यदि रु. 1 डाक्टरों को कमीशन बांटने, रु. 1 शासन के धूर्तों को खिलाने रु. 1 मीडिया पर भी खर्च करें तो भी 1 रु. फायदा होगा तो 1000प्रतिशत लाभ तो मिला, बाकी सारे पैसे खर्च भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा।

नि:संदेह फुग्गे के उपयोग अनावश्यक गर्भ ठहरने और यौन संसर्ग जनित बीमारियां मुख्य रूप से गनोरिया और सिफलिस बीमारियों से बचाव होने के साथ औरतों की रजस्वता स्थिति में संभोग करने से कपड़े खराब होने और दाग लगने से अवश्य बच जाते हैं।

सेना में 5000 सैन्य कर्मियों को एड्स की कोरी गप्प छोड़ने का सीधा सा मतलब है कि जिन यूरोपियन द्वारा पाकिस्तान की आई.एस.आई. और दूसरे आतंकवादी संगठनों को वित्तीय, सामरिक, सामाजिक और मानसिक सहायता देकर कश्मीर को अलग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें यूरोप के दो गुंडों अमेरिका और ब्रिटेन जिनकी कंपनियां ही कंडोम बनाती हैं और आतंकियों को सहायता देने के उपरांत भी 50 वर्षों के बाद भी कश्मीर की अलग इसीलिये नहीं कर पाए कि भारतीय सेना का उसमें न केवल अहं भूमिका भी रही है, जिसने हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।

भारतीयों ने हर क्षेत्र में विश्व के हर कोने में सफलता के झंडे गाड़े हैं। ये यूरोपियनस को असहनीय हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह चाहे एड्स फैलाकर ही क्यों न हो सेना को मानसिक तौर पर कमजोर कर देश की पूरा जनता का मनोबल तोड़ा जाए।

यदि एड्स कोई बीमारी है तो एशिया के मुस्लिम देशों में क्यों नहीं फैल रहा आतंकवादियों रुस, फ्रांस, जर्मनी व अन्य देशों में क्यों नहीं फैल रहा। फिर इतने करोड़ को एड्स हो ग़या, अरे हरामखोरों, धूर्तों, पाखंडियों मेरे देश में मरेंगे मरने दो तुम्हारी क्यों सिक या जल रही है। अपनी धोओ और बचाओ।

एड्स के नाम पर अरबों रुपए खिलाकर शासन में बैठे धूर्तों की फौज को स्वयं शासन ही देश को कमजोर बनाने पर तुला है। ठीक है कि उससे अनावश्यक बच्चे पैदा नहीं होंगे, परन्तु दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे।

कंडोम में लगाई जाने वाली चिकनाई ऐसा रसायन है जो भारतीयों को नपुसंक बना देगा ताकि इस देश को 20 वर्ष बाद नामर्द की फौज से ही जूझना पड़े। 50 वर्ष बाद नामर्द रहे और भारतीय औरतें पुन: यूरोप की बाहों में खेले और शंकर प्रजाति की फौज पैदा करे।

(पेज 1 का शेष)

भाजपा की 1 वर्ष की उपलब्धियां.....

की आवश्यकताओं और परेशानियों को ध्यान में रख नीति निर्धारण कर प्रशासन चलाया जाना चाहिए, परन्तु भ्रष्टों को वहीं बैठे रहने देकर सारी व्यवस्थाओं को जैसे दिग्गी दानव के शासन काल में चौपट किया वहीं अभी भी चल रहे है, जिनके विरुद्ध लोकायुक्त के पास शिकायतों के अंबार लगे हैं वे शान से मजे कर रहे हैं।

इस श्रेणी में क्षेत्रीय संयुक्त संचालक महाभ्रष्ट डॉ. शरद पंडित, महाभ्रष्ट आबकारी उपायुक्त उत्तम चंद अग्रवाल, सहा. आयुक्त एन.के. चौबे जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महा शूकर आशुतोष अवस्थी, इंदौर आदिम जाति कल्याण जिला संयोजक एस.के. शर्मा लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी नर्मदा परियोजना एस.एन. तिवारी, पंजीयन कार्यालय में करोड़ों का चूना लगाने वाला उपपंजीयक, एम.एल. श्रीवास्तव, भदौरिया, जल संसाधन का महाभ्रष्ट ए.के. सोजतिया, मुख्य अभियंता नर्मदा ताप्ती कछार वर्तमान में पदोन्नत होकर इंजीनियर इन चीफ बना बैठा है। म.प्र. गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त यादव, खाद्य विभाग के भ्रष्टों में जो वर्षों से जमे हुए हैं, पी.डी. मीणा, सी.एल. जाटव, पी.के. शुक्ला सभी सहायक खाद्य नियंत्रक इंदौर, धार के आदिम जाति कल्याण आयुक्त बीजी मेहता, लोक निर्माण का का.यं. मरावी, जल संसाधन जावर, उज्जैन के सिंहस्थ में हुए लोक निर्माण भ्रष्टाचारों में मुख्य अभियंता सोनगरा, एन.के. श्री माली अय्याश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, भ्रष्ट का.यं. एस.के. जाटव जैसे सैंकड़ों अधिकारी अपने-अपने पदों पर वर्षों से जमे हुए लूटपाट में लगे हैं। परन्तु गौर को मिलती वसूली के आगे फुर्सत नहीं भ्रष्टाचार पर गौर फरमाने की।

विद्युत मंडल में नर्मदा पर बंधने वाले बांध से विद्युत तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों से उत्पादन बढ़ाने का कहने की अपेक्षा बार-बार गौर निजी महाभ्रष्ट कंपनी रिलायंस को कह रहा है। विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत विद्युत मंडल और निगम से कहने की अपेक्षा ताकि ये हरामख़ोर भी प्रति यूनिट 25 पैसे से 50 पैसे तक का कमीशन खा सकें।

जबकि तीसरे आयाम में जरूरत है तो प्रदेश की जनता की भविष्य की आवश्यकताओं और परेशायिों को ध्यान में रख चहुंमुखी विकास की आधार शिला रखी जाए, ताकि अगले 5 वर्षों में तो कम से कम जनता हा-हाकार न मचाए। इस त्रिआयामी सूत्र पर क्या म.प्र. सरकार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान सरकार काम कर पा रही है जबकि तीनों सरकारों ने 1-1 वर्ष पूरा कर लिया है।

केन्द्र में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही भविष्य में लूट-खसोट करने केलिए मोहरें जमा लिए वर्तमान में जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुरानी सरकार में हुए भ्रष्टाचार की पर्तें उधेड़ना शुरू कर दी और शंकराचार्य जैसे मु- में उलझाकर विपक्ष को ठंडा कर दिया ताकि उनकी लूटपाट पर कोई ध्यान न दे। वे पेट्रोलियम, गैस, कृषि में अनुदान का रोना रोकर चारों तरफ से माल बटोरने में लगे हैं। जो मुंह खोलता है उसके कालर की गंदगी दिखाकर, सीबीआई की जांच बैठाकर चुप कर देते हैं।

गौर को इस त्रिआयामी सूत्र के आधार पर कार्य करना चाहिए। अन्यथा बिजली की कमी के चलते भी बिजली की दरों में वृद्धि करना उल्टा ही अभिशाप बन जाएगा। विद्युत मंडल के भ्रष्ट इंजीयिरों को नकेल पहनाने की तो दूर ये स्वयं उसके इशारे पर नृत्य करने लगे हैं। तो वो मूर्ख हुए हैं जो अपनी कारस्तानियों की तरफ ध्यान देने के लिए बिजली की कमी दूर कर भाजपा सरकार को मौज-मस्ती करने का मौका देंगे।

उपलब्धियां गिनवाने से पहले अपने कालर की जमी कालिख हटाओ और जनता के वादों पर खरे उतरो। नहीं तो अपना चुनावी घोषणा पत्र के आइने में पूरा भाजपा शासन अपना चेहरा देख ले जनता को मत देखो।

(पेज 1 का शेष)

ईराक में अमेरिकी तांडव.....

भर मर्दो, औरतों और बच्चों ने 1 वर्ष अमेरिकी आतंक का डटकर मुकाबला किया है। पर वह वियतनाम की अपने देश का हिस्सा बनाने का मंसूबा पूरा नहीं कर पाया, परन्तु साल भर ही ईक को उसने अपना 53वां राज्य घोषित कर दिया संयुक्त राष्ट्र के कोफी अन्नान को लानत है कि वह भी ईराक में अमेरिकी और संयुक्त सेनाओं द्वारा किए जा रहे नरसंहार के विरुद्ध एकदम चुप हैं अब गिद्ध अमेरिकी क्या मानव अधिकार का पालन कर रहे हैं। दुनिया को पट्टी पढ़ाने वाला ईराक और अफगानिस्तान में क्या कर रहा है। 10-12 साल की लड़कियों पर 15, 20-20 दरिंदे बलात्कार कर रहे हैं। महिलाओं को वेश्यों की तरह फौजें रौद रही हैं, उनके घरवालों को सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है। ये मानव अधिकारों का पालन हो रहा है, ये सब कुछ पूरे ईराक के हर शहर में अमेरिकी फौजों का रोज का तांडव है। खाना उसी को दिया जाता है जो महिलाएं उन सैनिकों की टुकड़ी की हवस शांत कर देती है। भारत शांति का मसीहा कांग्रेसी टुच्चों और हड्डी चूसने वाले अन्य दलों की शासन व्यवस्था से पहले ही दो-चार हो रहा है। देश को चलाने वाले ये सारे अपराधी देश में ब्लैक मार्केटिंग और वसूली का जाल बिछाने में लगे हैं। फिर दूसरी तरफ ये भिखारी अमेरिकियों की गंदगी चाटने वाले क्या खाकर अमेरिका को आंख दिखाएंगे। ये तो उसकी गंदगी चाटने अमेरिका ही जाकर उनके चरण वंदन कर लेंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि फ्रांस, चीन, जर्मनी, रुस जैसे देशों में भी इस व्यापक अमेरिकी जन संहार के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया कहीं देखने को नहीं मिल रही। धन्य सबने अमेरिकी गुंडों के सामने घुटने टेक दिए।

(पेज 8 का शेष)

मंत्रियों का इंदौरी प्रेम.....

इसी दिन 17-12-04 को हरनामसिंह राठौर जेल मंत्री इंदौर में थे। सारे जेल अधिकारी रेसीडेंसी में थे। ये वही जेल विभाग है जहां इंदौर में 1800 कैदियों के औसत से रु. 36 प्रति कैदी मिलता है और ये भ्रष्ट रु. 6 प्रति कैदी का भी खाना नहीं खिलाते, फिर तेल, साबुन, वस्त्र, कंबल आदि का पैसा भी डकार जाते हैं। साथ ही कैदियों से मिलने आने वाले ही आटा, दाल, शकर, घी सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक पहुंचाते हैं, जिसका एक तिहाई वहां पर तैनात कर्मी छीन लेते हैं। एक तिहाई पुराने खूंखार दादा पहलवान कैदी छीन लेते हैं, जिस कैदी का सामान होता है उसे एक तिहाई ही हाथ में आता है।

चूंकि श्री अजमेरा सायं 6.30 बजे कैमरा, स्टैंड लिए खड़े थे। साक्षात्कार के लिए भ्रष्ट व्ही.एस. अरोरा संचालक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अंदर जाकर शायद शिकायत की, दौरा खत्म बिना बातचीत किए भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से गाड़ी में बैठकर रवानगी डाल दी। यदि रु. 54000 प्रतिदिन जेल अधीक्षक बचा रहे हैं तो रु. 25000 प्रतिदिन के हिसाब से जेल मंत्री और मुख्यमंत्री को भी तो पहुंचाना पड़ेंगे। उसी का बेग लेने आए होंगे बेचारे।

इंदौर प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री जयंत मलैया को इंदौर हर माह आना ही होगा। स्वाभाविक है जिलाधीश राजेश राजौरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का भ्रष्ट वीरेन्द्र कुलश्रेष्ठ से लेकर कालोनाइजर बिल्डर को दरबार में मिलन के लिए बख्शीस भेंट करनी ही पड़ेगी।

(पेज 8 का शेष)

प्रौढ़ महिलाओं में.....

शक होगा तो ठीक हर बार उसे वही पसंद आएगा तो फिर अब इतनी क्षमता नहीं कि एक दो घंटे बाद आगे की पूर्ति भी कर दें। जबकि प्रेमी से मुख मैथुन करने-कराने में आगे-पीछे का सुख एक ही बार में थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद चूंकि वो 18 से 30 वर्ष का है कर देगा अब पति 40 से ऊपर हो गए हैं उन्हें कमाई, धन और दोस्तों, कारोबार और व्यवसाय से ही फुर्सत नहीं। घर आते हैं खाना-वाना खा पीकर उन्हें सोना दिखता है वो एक बार पूरी तरह निगाह भर कर देखते भी नहीं। यौन संतुष्टि की बात तो दूर। तो स्वाभाविक है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लड़कों को फांसो और निपटाओ। जब पूछा गया कि पति को मालूम पड़ेगा तो घर नहीं टूटेगा तो उनका खुलकर कहना था तो हमें संभालना आता है। कहां जाएंगे इतना कश बचा है क्या?

सर्व शिक्षा (लूटो) अभियान

सर्व शिक्षा अभियान में जो पहले राजीव गांधी शिक्षा मिशन के नाम से चल रहा था। सारा पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को मिला था और मिल रहा है। म.प्र. शासन को रु. 1000 करोड़ मिले। जिसमें से इंदौर को पहली ही रु. 80 करोड़ की किश्त मिली। अब हर वर्ष कार्य की योजना के हिसाब से रु. 10-12 करोड़ की किश्त मिलती है। जिसमें स्कूल भवन जिसमें प्राथमिक शाला जिसमें रसोई घर, पेयजल व शौचालय के हिसाब से रू. 2 लाख, माध्यमिक शाला भवन के लिए रु. 4 लाख, अतिरिक्त कक्ष के लिए रु. 10,000 रसोई के छप्पर के लिए रु. 25 लाख, वार्षिक शाला के रखरखाव के लिए रु. 5000 स्वीकृत किए गए सन 2004-05 में। जिसकी राशि संयुक्त रूप से जिलाधीश जिसका मुखिया होता है के माध्यम से जिला संयोजक संबंधित पंचायतों में शिक्षा के हेतु कार्य करवाता है जिसमें पुस्तकें, कर्मियों का वेतन आदि के रूप में करोड़ों रुपए जिलाधीश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशुतोष अवस्थी, जिला संयोजक प्रदीप कुलकर्णी जैसे हरामखोरों की फौज पी जाती है। जनता को मालूम ही नहीं पड़ता फिर इसमें सर्व शिक्षा अभियान, सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बालिका शिक्षा, बच्चों का दोपहर का भोजन, पुस्तकें कापियां, गणवेश, छात्रवृत्ति जैसे अनेकों कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए हर जिले को मिलते हैं। शाला भवनों को रखरखाव तक के लिए रु. 5000 प्रति वर्ष मिलने लगे हैं। परन्तु गांवों में जाकर देखें स्कूलों की दशा भारी दयनीय ही मिलती है। पीने का पानी, शौचालय, रसोई की व्यवस्था तो 70 प्रतिशत शालाओं में शहरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। स्वाभाविक है हर जिले के पंचायतों, जनपद पंचायतों का पैसा हर जिले का महाधूर्त जिलाधीश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजगर बन कर हजम कर जाते हैं। नीचे पूरे प्रदेश को सर्वशिक्षा अभियान में मिले पैसे और आयोजन की म.प्र. की संचालक नीलम राव द्वारा दी गई स्वीकृति के आंकड़े दिए जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2004-05 में प्रदेश के समस्त जिलों में निम्न अनुसार निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्माण कार्यों की जिलेवार सूची संलग्न है।

क्र.	निर्माण कार्यों के प्रकार	इकाई लागत (वर्ष 2004-05 में) स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए)	स्पिल ओवर वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05 के लिए नवीन स्वीकृत निर्माण कार्य	कुल स्वीकृत
1.	बी.आर.सी. भवन		41		41
2.	प्राथमिक शाला भवन (किचन शेड, पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय सहित)	रु. 2.00 लाख			
	अ) प्रा. शाला के लिए		8253	255	8508
	ब) ई.जी.एस. का प्रा. शाला में उन्नयन		4426	4103	8529
3.	माध्यमिक शाला भवन (पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय सहित)	रु. 4.00 लाख	818	1515	2333
4.	अतिरिक्त कक्ष	रु. 0.90 लाख			
	अ) प्राथमिक शाला के लिए		2612	1924	4536
	ब) माध्यमिक शाला के लिए		1698	1450	3148
	स) संकुल केन्द्र के लिए		533		533
5.	किचन शेड	रु. 0.25 लाख		9853	9853
6.	पेयजल व्यवस्था (प्राथमिक एवं माध्यमिक)		4814		4814
7.	वार्षिक रख-रखाव व मरम्मत कार्य	रु. 5000/-			
	अ) प्राथमिक शाला के लिए			61029	61029
	ब) माध्यमिक शाला के लिए			8939	8939

स्पिल ओवर तथा वर्ष 2004-05 में स्वीकृत निर्माण कार्य

S.N.	District	BRC Buildings	PS Building			Buildings for EGS to PS Upgration			MS Buildings (including Drinking Water & Toliet cost)		
		Spill over No.	Spill over No.	Fresh Plan 2004-05	Total	Spill over No.	Fresh Plan 2004-05	Total	Spill over No.	Fresh Plan 2004-05	Total
1.	बैतूल		191	25	216	0	27	27	57	110	167
2.	रशियन		221	21	242	0	0	0	2	95	97
3.	सिहोर		206		206	50	92	142	5	35	40
4.	राऊ		302		302	340	204	544	14	17	31
5.	सतना		438		438	50	251	301	5	0	5
6.	उमरई		60		60	0	55	55	14	16	30
7.	पन्ना		190		190	151	78	229	0	65	65
8.	मंदसौर		96		96	18		18	37	35	72
9.	नीमच		22		22	16		16	31	40	71
10.	रतलाम		114		114	71	39	110	26	50	76
11.	भिंड		195		195	6	183	189	10	8	18
12.	दमोह		84	7	91	77	185	262	54	20	74
13.	दतिया		68		68	30	15	45	22	35	57
14.	देवास		122		122	0		0	14	50	64
15.	झाबुआ		89		89	80	231	311	107	65	172
16.	खंडवा		89	0	89	174	32	206	10	51	61
17.	खरगोन		261		261	217	315	532	15	0	15
18.	बड़वानी		116		116	306	258	564	15	0	15
19.	मंडला		258		258	92	53	145	15	40	55
20.	डिंडोरी		154		154	14		14	7	25	32
21.	मुरैना		253		253	20	131	151	7	10	17
22.	श्योपुरकला		113		113	6		6	8	35	43
23.			232		232	0	94	94	10	30	40
24.	शाजापुर		204		204	0	140	140	42	25	67
25.	शिवपुरी		142		142	55	228	283	20	40	60
26.	विदिशा		303	64	367	0	135	135	12	0	12
27.	बालाघाट	9	171		171	200	75	275	0	0	0
28.	ग्वालियर	5	272		272	84	75	159	10	25	35
29.	भोपाल	2	188	0	188	0	0	0	0	42	42
30.	नरसिंगपर	6	175		175	110	15	125	0	0	0
31.	होशंगाबाद		240		240	30	0	30	0	50	50
32.	हरदा		3		3	48	29	77	6	40	46
33.	इंदौर	1	88		88	124	30	154	20	30	50
34.	छिंदवाड़ा		202		202	390	150	540	0	0	0
35.	उज्जैन	6	355		355	0	0	0	0	35	35
36.	जबलपुर	6	165		165	160	108	268	0	10	10
37.	कटनी	6	251		251	140	70	210	0	0	0
38.	सागर		270		270	380	13	393	0	25	25
39.	राजगढ़		69	0	69	122	45	167	5	65	70
40.	गुना		269	0	269	257	193	450	10	77	87
41.	दार		514	138	652	0	0	0	0	50	50
42.	शहडोल		128	0	128	359	75	434	5	80	85
43.	सीधी		56		56	195	409	604	75	15	90
44.	छतरपुर		120		120	0	2	2	93	50	143
45.	टीकमगढ़		194		194	54	68	122	35	24	59
	कुल	**41**	**8253**	**255**	**8508**	**4426**	**4103**	**8529**	**818**	**1515**	**2333**

साप्ताहिक समय माया

प्रौढ़ महिलाओं में बढ़ रही अय्याशी

पेइंग गेस्ट, किरायेदार, ट्यूटर कोच के रूप में शोषण

युवाओं के बदलते रिश्ते, 24 घंटों, टीवी पर परोसा जा रहा यौन संबंधों का खेल, रेडियो मिर्ची के अश्लील कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार माध्यम में छाया यौन उत्तेजना का खेल, 35 के बाद ढलते यौवन में यौन आकांक्षा बढ़ जाती है। सिके लिए पॉश इलाके की महिलाएं नई उम्र के लड़कों का यौन शोषण करने के लिए पेइंग गेस्ट, किरायेदार, यदि बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाने केलिए ट्यूटर के, शरीर को आकर्षक बनाए रखने के लिए जिम का कोच, इंग्लिश, कंप्यूटर या अन्य कुछ सीखने समझने के बहाने, नई उम्र के लड़कों को पकड़कर उन्हें घर बुलाकर या उनके कमरों को किराये पर देकर या केन्द्रों पर जाकर 35 से 50 की उम्र की महिलाएं-पुरुषों को निचोड़ती हैं।

यही हाल पुरुषों द्वारा चलाए जाने वाले महिलाओं के कालेज, संस्थाओं, विद्यालयों, कम्प्यूटर केन्द्रों पर नई उम्र का यौवनाओं को भोगने केलिए पुरुष भी कर रहे हैं।

कुल मिलाकर अंकल-आंटियों का चलन नई उम्र के युवक-युवतियों में बढ़ रहा है। निःसंदेह उनके हाथ खर्चे होटलों, टाकीजों, नये वस्त्रों, वाहनों क़ा शौक पूरा करने के काम आता है। आखिर पालकों से ज्यादा धन मांगना संभव नहीं फिर धन मांगने से पोल खुलने का भी डर बना रहता है।

ईंदौर। यौन शोषण के मामलों में म.प्र. सबसे अग्रिम पंक्ति में है। इंदौर महानगर नवयौवनाएं लड़कों के कमरे पर रात भर 5-6 युवकों के बीच यौनाचार करती मिल जाएंगी। अधिकांश महिला छात्रावासों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। धनाढ्य छात्राएं तो मनपसंद को बोगने के लिए पैसे भी खर्च करती हैं। ज्यादा उच्च वर्ग में हैं तो उन्हीं छात्राओं की माताओं के संबंध भी उन्हीं पुरुषों से होते हैं जिनको उनकी बेटी भोग रही होती हैं। महिला छात्रावासों में यौनाचार के लिए लड़कियों के आना-जाने का सिलसिला शाम 6 बजे से शुरू होकर सुबह 8-9 बजे तक चलता रहता है। चलिए ये सब तो कुआंरिया थीं।

शादी-शुदा महिलाओं में 35 से 50 वर्ष की उम्र में नए-नए युवाओं को भोगने का सिलसिला भी काफी प्रगति पर है, जिनके पति अक्सर घरों से बाहर रहते हैं या जिनके पास कम समय होता है। घरों में कम समय दे पाते हैं टीवी पर प्रस्तुत यौनाचार, रेडियो, प्रचार-प्रसार माध्यमों से यौन उत्तेजकता यौनाचार के लिए 24 घंटों उत्तेजित करती हैं स्वाभाविक है पॉश कालोनियों की ऐसी महिलाएं नई उम्र के युवकों को फांसने और यौन शोषण करने के लिए अपने यहां खाली पड़े कमरों को किराए पर देकर पेइंग गेस्ट के रूप में, टिफिन सेंटर चलाकर, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन, कम्प्यूटर को, बदन की कमनियता बरकरार रखने केलिए जिमों, हेल्थ क्लब में जाकर, 8वीं से स्नातक स्तर के युवाओं को कोचिंग के बहाने, इंग्लिश, कम्प्यूटर या अन्य पाठ्यक्रमों को सीखने या सिखाने के बहाने बुलाकर या अन्य किसी बहाने से संपर्क कर उनकी कद काठी देखकर भरपूर यौन शोषण किया जाता है। निःसंदेह इससे युवाओं को कुछ आमदनी हो जाती है जो उनकी पढ़ाई व अन्य जीवनयापन के खर्चों के काम भी आती है। इसके विपरीत निर्धन वर्ग की महिलाएं ऐसे नवयुवकों से वसली भी कर लेती हैं। पर धन मुख्य आकर्षण की जगह प्रौढ़ महिलाओं की यौनाचार की इच्छापूर्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है। निःसंदेह युवा वर्ग में भी आंटियों का क्रेज कई कारणों से होता है। जिससे सर्वप्रथम होता है यौनाचार में पूर्ण सहयोग और परस्पर आनंद विनिमय। जबकि वही यौनाचार करने में पतियों को ना-नुकुर झेलनी पड़ती है। इन प्रौढ़ महिलाओं की आनंद नगर, साकेत नगर, सुखलिया, पलासिया, खाती वाला टैंक, इंद्रपुरी कालोनी, आर.टी.ओ. की कालोनियां, एम.आई.जी., एल.आई.जी., विजयनगर, तुकोगंज, छावनी, मल्हारगंज, स्कीम नं. 54, 71, 74 की पॉश कालोनियों में और जहां-जहां ऐसे शिक्षण संस्थानों जिसमें युवा वर्ग अध्ययनरत है, उसके आजू-बाजू की कालोनियों में चारों तरफ इस यौनाचार का बोलबाला है।

इन सबमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रौढ़ महिलाओं का नवयुवकों के प्रति और नवयुवकों का आंटियों के प्रति आकर्षण आखिर न केवल इंदौर वरन पूरे विश्व में क्यों बढ़ रहा है इसको पीछे जो तथ्य सामने आये नवयुवकों का कहना था कि आंटियां भारी खातिरदारी करने के साथ धन की व्यवस्था तो करती ही हैं साथ ही आँटियां सच मायने में खुलकर यौनाचार के समय वस्त्रहीन होकर व करके मुख, गुदा मैथुन करने कराने के लिए बाध्य कर लंबे समय तक भोगती हैं। जो इच्छाएं वो अपने पति के सहवास से पूरी नहीं कर पाती वो सारी इच्छाएं वो इन नवयुवकों के सहयोग से पूरी कर संतुष्टि महसूस करती हैं। ढलती उम्र में प्रौढ़ महिलाएं भारी उत्तेजक होकर बहुविधि यौनानंद चाहती हैं, दूसरा पति की व्यस्तता, कमजोर पढ़ते शरीर और पारिवारिक पीढ़ाओं से मुक्ति पाने के लिए आंटियों में दिनों दिन युवाओं के यौन शोषण की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

सिके विपरीत कुछ प्रौढ़ महिलाओं से युवकों को भोगने की बात पूछी गई तो पहले तो उन्होंने सिरे से नकारा परन्तु घुलने-मिलने के बाद उन्होंने सच्चाइयों का बयान किया। खुल कर कहा कि पति परमेश्वर वाली बात और एक व्यक्ति के साथ ही यौन संबंधों की बात सिरे से खारिज भी कर दी। उनका कहना था कि ठीक है परिवार में पति को निभाना जरूरी है अन्यथा बच्चों का भविष्य बिगड़ने के साथ ही समाज में बदनामी और भविष्य असुरक्षित हो सकता है, परन्तु पर पुरुष से संबंध रखना पाप-पुण्य नहीं बन जाता। सारी जिंदगी एक पुरुष के यौन संबंधों पर गुजारना कहीं महान नहीं बना देता। टीवी पर जो महिलाएं कार्यक्रमों में आती हैं जिनके पास नाम पैसा पापुलरिटी तीनों ही हैं, क्या एक पुरुष से संबंध रखने के कारण मिली है क्या जब वो सैंकड़ों के साथ सोकर और खुश करके समाज पर छा जाती है तो शरीर की भूख मिटाने के लिए हमने दो-चार पुरुषों से संबंध स्थापित कर लिए तो कौनसा गुनाह कर दिया। जो सुख पति से नहीं मिला मैंने प्रेमी से लिया उसने खुलकर सब कुछ किया। अगर पति के साथ करेंगे तो उसे शक होगा कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। फिर पति को एक बार पीछे की हां कर दी तो

(शेष पेज 6 पर)

मंत्रियों का इंदौरी प्रेम

आखिर वाणिज्य मंत्री कैलाश चावला इंदौर के प्रभारी जयंत मलैया, जेल मंत्री हरनाम सिंह राठौर हर महीने दो महीने में इंदौर क्यों आते हैं।

पाठकों को याद होगा दिग्गी दानव भी हर महीने में कम से कम एक दौरा जरूर किसी न किसी बहाने करने आते थे, चाहे वो विमान में बैठे-बैठे या हवाई अड्डे पर उतरकर अपनी रायल्टी का जिलाधीश से मनोज श्रीवास्तव से रु. 5 करोड़, सुलेमान से रु. 6.50 करोड़ हर मार वसूलने आते थे।

वही हाल कैलाश चावला का है। हर माह वाणिज्यकर के उपायुक्तों आर.सी. पालीवाल, एस.एल. वर्मा, जी.एस. बघेल से यहां बैठने और वसूली कर उनका हिस्सा वसूलने ही आते हैं। इसलिए ये तीनों अपनी-अपनी वसूली लेकर चरणों में समर्पित करते पहुंच जाते हैं। यह अवश्य ध्यान देने वाला तथ्य है कि वो ऐसे वसूली कार्य के लिए अपना पारिवारिक दौरा बनाकर आते हैं।

दिनांक 17-12-04 को कैलाश चावला ने जैसे ही इंदौरी धरती पर कदम रखा तीनों उपायुक्त कदमताल करते आगवानी को पहुंचे। साथ में दोपहर का भोजन किया बख्शीश दी और बिदा।

(शेष पेज 6 पर)

वाहन विक्रेता करते हैं सर्विसिंग की आड़ में जालसाजियां

बजाज, हीरो होंडा, टीवीएस, एलएमएल, मारुति, क्वालिस डीलर सर्विसिंग के नाम पर बदल लेते हैं असली और नये पुर्जे

इंदौर की व्यावसायिक राजधानी में सभी प्रकार के व्यावसायिक कुकर्म होते हैं चाहे वह सराफा बाजार हो, कबाड़ी बाजार हो या नई, पुरानी गाड़ियों के विक्रेता। हर किसी धूर्त को जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने की पड़ी है। इसलिए जितने कुकर्म हो सकते हैं वे करते हैं। नई गाड़ी विक्रेता चाहे दो पहिया हो या चार पहिया गाड़ी की कीमत पर मिलने वाले कमीशन से किसी भी धूर्त, जालसाजों, मक्कारों का पेट नहीं भरता चाहे वह पटवा अभिकरण, कासलीवाल होंडा, सोजतिया, राजपाल, सांघी ब्रदर्स, जबलपुर ट्रेक्टर्स, जैसे सभी टीवीएस, एल.एम. एल, बजाज, मारुति, होंडा, हुन्डई, होंडा, यामाहा, हीरोहोंडा, काइनेटिक होंडा, एच.एम.टी. ट्रेक्टर्स, सोनालिका ट्रेक्टर्स, आयशर, टाटा आदि दो पहिया, चार पहिया वाहन विक्रेता कंपनी द्वारा निर्धारित कीमत पर तो कमीशन खाते ही हैं साथ उसमें 20 प्रतिशत कीमत की एसेसरीज के भी 100 प्रतिशत उनके द्वारा निर्धारित कीमत की भी वसूली अलग से अलग खाते में वसूलते हैं ताकि हरामखोर कर चोरी कर सके।

फिर मुफ्त सर्विसिंग के नाम पर पहली दूसरी सर्विसिंग तो कंपनी के मापदंडों के अनुसार कर देंगे पर चौथी-पांचवी सर्विसिंग में अधिकांश विक्रेता मुफ्त की आखिरी सर्विसिंग के नाम पर इंजिन बदलने सेलेकर बैटरी व अन्य कल पुर्जे बदल डालते हैं क्योंकि उसके बाद उनकी जिम्मेदारी समाप्त वाहन में परेशानी आने पर खुद की जेब से वाहन मालिक को पैसा खर्च करना पड़ता है। जिसके नाम पर ये अच्छी-खासी कमाई कर वाहन मालिक को तबियत से काट लेते हैं।

इंदौर। प्रदेश की इस व्यावसायिक राजधानी में अधिकांश हर प्रकार के व्यवसायी भारी जालसाजियां और ग्राहकों के साथ भारी लूट-खसोट भी करते हैं। निःसंदेह ग्राहक को बार-बार नोचने और लूटने से ग्राहक भी भारी सयाना और संभल-संभल कर चलने वाला और चालाक प्रवृत्ति का है, परन्तु ऐसे ग्राहकों की संख्या हर क्षेत्र मे 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं। फिर इंदौर का सराफा हो, वाहन व्यवसायी डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेकर सब्जी मंडी तक में बासी पुरानी सब्जी को ताजा दिखाने केलिए सेव पर लाल रंग, मटर, मिर्टी, धनिया सौंफ पर हरा रंग पोत कर बेचने से नहीं चूकते। फिर यदि यही बात वाहनों पर लागू होती है तो फिर तो बात ही निराली है। वाहन बेचने की जालसाजियों से लेकर बाद की पहली दूसरी मुफ्त सर्विसिंग के बाद की सर्विसिंग में जो चौथी या पांचवी हो सकती है अंतिम सर्विसिंग में नई गाड़ी के इंजिन बदलने से लेकर कार्बोरेटर, प्लग और बियरिंग तक कुछ भी बदला जा सकता है। इसमें सबसे कुख्यात है इस शहर में राजपाल, जबलपुर ट्रेक्टर्स, परन्तु ये बात सभी वाहन विक्रेताओं पर लागू होती है। वाहन बिक्री के साथ जबरदस्ती एसेसरीज कंपनी द्वारा बेची जाती है के नाम पर ये हरामखोर धूर्त चिपकाते ही हैं। जो माल बाजार रु. 100 का मिलेगा उसको येरु. 500 के भाव में चिपकाएंगे। जैसे कि सोजतिया से सीटी 100 खरीदी तो जो लेग गार्ड रु. 50 का, साड़ी यदि रु. 200 तैर रु. 500 में लगाया गया। इस प्रकार गाड़ी की कीमत पर कमीशन खाने के बाद भी इस लुटेरे ने रु. 550 ज्यादा वसूले। यही हाल सभी दो पहिया और चार पहिया वाहन विक्रेताओं का है जिसकी रसीद अलग खाते से काटी गई। इस प्रकार घर के किसी बच्चे या कुत्ते बिल्ली के खाते में जमा कर डकार लिया जाता है। यह तो हुई मालिक के इशारे पर की गई लूट। फिर जब मालिक इतना लूट रहा है तो कर्मचारी भी खालिस वेतन पर कैसे लेगा। वह भी पेट्रोल चोरी करने से लेकर इंजिन ऑइल तक कम भर कर भी चोरी करेगा, सर्विसिंग के समय स्पेयर पार्ट्स बदलने से लेकर कार्बोरेटर, फिलर बदलने सेलेकर ये वर्तमान भुखोरों की फौज इंजिन तक सब बदल सकती है। फिर ग्राहकों को ये निकम्मी हरामखोर फौज कैसे परेशान करती है कि सर्विस मेन्युअल में गारटी के सारे फार्म नहीं भरे जाएंगे। बिल इंश्योरेंस जिसके अधिकांश डीलर घर परिवार के किसी सदस्य के नाम से एजेंसी लेकर खुद ही बीमा करेंगे और बीमें की पालिसी के कागजात नहीं देंगे फिर परिवहन पंजीयन में भी रु. दो पांच से मार लेंगे क्योंकि आरटीओ एजेंट भी घर परिवार का या उनके ही यहां का कोई कर्मचारी होता है जिसका कमीशन भी ये हरामखोर खुद डकार लेंगे। इस पर यदि गाड़ी किसी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित है तो फिर इनकी पौ बारह क्योंकि इन सबकी कीमत जो इन भ्रष्ट लुटेरों की एसेसरीज, बीमा, आरटीओ की कुल फीस और कमीशन मिला कर ही होगी। ग्राहक को तो इन सभी हरामखोरों के कमीशन के साथ वित्त उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के कर्मचारियों की जालसाजियों जिसमें फाइल बनाने से लेकर उनके कार्यकर्ताओं के पेट्रोल बिल, अनाप-शनाप ब्याज की दरें जो गाड़ी की कुल कीमत के आधे से दुगुने के बराबर कुछ भी हो सकती है। इन वित्त पोषण करने वालों लुटेरों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सेंचुरियन बैंक से जीई फाइनेंस, सिटी बैंक फाइनेंस तक करीब 25 से ज्यादा वित्त पोषण करने वाले हैं जो ग्राहक से चेक लेकर दोनों हाथ से उनका शोषण तो करते ही हैं। साथ ही किश्तें न जमा होने, चेक लौटने पर जमा किया गया सारा पैसा हजम और वाहनों को गुंडों के माध्यम से चोरी करवा कर पुलिस की सहायता से उठवा भी लेते हैं। अपनी इन बदतमीजियों की पोल न खुले इसलिए पत्रकारों, पुलिस, वकीलों और समझदार पढ़े-लिखे बड़े लोग को ये भ्रष्ट, लुटेरे, मक्कारों की फौज किसी भी वाहन पर वित्त पोषित नहीं करते हैं।

वाहन डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन वित्त पोषण करने वाली कंपनियों बैंकों के लोगों को अपने यहां इसीलिए काउंटर खुलवा देती है कि ऐसे वित्त पोषण करने और ऋण देने की आड़ में ये लुटेरे वाहन विक्रेता चूंकि ग्राहक ऋण लेकर वाहन खरीद रहा है। एसेसरीज पर 5 से10 गुना लाभ कमा लेते हैं। बीमे और आरटीओ के नाम पर भी 10 से 25 प्रतिशत तक कमाई कर लेते हैं।

साधारण ग्राहक किससे वाहन खरीदे क्योंकि यहां तो हर साख पर गिद्धों का बसेरा है। उपभोक्ता संरक्षण के न्यायालय भी तो भारतीय न्यायालयों की तरह तारीखों पर तारीखें देकर ग्राहकों और पीड़ितों को भारी संत्रास देते हैं। इसलिए ग्राहकों को इन शूकरों कीफौज द्वारा लूटने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचता। कंपनियां अपने वाहन विक्रेताों की इन बदतमीजियों और लूट पर कभी कोई टिप्पणी इसलिए भी नहीं करती कि उन्हें अपने माल बिकने से मतलब रहता है। फिर चाहे हीरो होंडा, होंडा, टीवीएस, मारुति, हुन्डई, टाटा, कायनेटिक, यामाहा, सुजुकी, बजाज, एलएमएल जैसे कोई भी कंपनी हो।

रोजगार की गारंटी या हरामखोर की गारंटी के अधिकार मांगने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। दिनांक 17-12-04 को शाम 5 बजे मोती बंगले के सामने।

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. ए-72 आर.एस.एस. नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिन्टर्स जेल रोड, इंदौर द्वारा मुद्रित
कम्प्यूटराईजेशन एवं ग्राफिक्स अंबिका ग्राफिक्स भोपाल प्रातिनिधि मो. नावेद खान मो.-98262-25266, जबलपुर प्रतिनिधि श्री चंद्रभूषण सकरगाय फोन-98932, 57357.